RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष : 23 अंक : 3
5 नवंबर 2022

जगत विज़न

भारत जोड़ो यात्रा

यात्रा से मंजिल मिलेगी जरूर

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 23 अंक 03 05 नवम्बर 2022

देश में फिर हुई नवीन क्राँति की शुरूआत

(पृष्ठ क्र.-6)

■ राजस्थान में बीजेपी को वसुंधरा राजे सिंधिया को......................40

■ लापरवाही के जिम्मेदार कौन? 42

■ त्रिकोणीय होगा मुकाबला-गुजरात चुनाव 48

■ उज्धैन : भारत का एक अत्यंत प्राचीन गौरवशाली नगर 54

■ ग्रामीण पेयजल के लिए समय अनुरूप बदलते संशाधन 58

■ केजरीवाल ही असली हिंदु हृदय सम्राट है 61

■ Festivals and the Environmental Pollution.....................62

छग
सरकार

संपादकीय

मोरबी पुल हादसा का कौन है जिम्मेदार?

जंगल में मोर नाचा किसने देखा। गुजरात के मोरबी में पुल गिरा– सबने देखा। 135 से ज्यादा कीमती जानें चली गईं। गुनहगार कौन? तस्वीरें–वीडियो दिखाकर तर्क दिए गए कि पुल पर उस शाम को मौजूद लोग ही हादसे का सबब थे। पुल जिसे चंद दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया हो। जाहिर है हादसे के लिए मोरबी के वो भ्रष्टाचारी मोर ही जिम्मेदार हैं जिनके पास पुल के रखरखाव का मोटी कीमत पर ठेका था। मान भी लिया जाए कि पुल पर क्षमता से कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए तो ये देखना किसका जिम्मा था? क्या उस दिन अधिक टिकट बेचने के चक्कर में सुरक्षा से जुड़े इस अहम तथ्य की अनदेखी की गई। 17 रुपए का टिकट (बच्चों के लिए 12 रुपए) झूलतो पुल पर जाने के लिए लेना पड़ता था। यानि पुल पर ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों की मौजूदगी हादसे के वक़्त मान ली जाए तो कुल टिकट बिक्री सात–आठ हजार रुपए की हुई होगी। क्या इस छोटी सी रकम के लिए इतनी जानों को दांव पर लगा दिया गया? जिस बिजनेस ग्रुप के पास पुल की मेंटनेस का दायित्व था वो घड़ियां, ई–बाइक और विट्रीफाइड टाइल्स आदि का निर्माण करता है।ये ग्रुप अपने एक विज्ञापन में दावा करता नजर आता है कि इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी है ग्राहक की संतुष्टि और ग्राहक का भरोसा। इसी ग्रुप ने मोरबी के पुल को लेकर कैसे ग्राहक के भरोसे का ख़्याल रखा, दुनिया के सामने है। अब एक नदी के ऊपर मौजूद झूलते पुल की मरम्मत और रखरखाव का काम सिविल इंजीनियरिंग में दक्ष लोगों के हाथ में होने की जगह घड़ियां बनाने वाली कंपनी को दे दिया जाए।

मोरबी के झूलते पुल का हादसा चीख–चीख कर बता रहा है कि वह सिस्टम का नाकाम होना है। बड़े–बड़े प्रोजेक्ट अपने चहेतों को देना,बड़ी मूर्तियां, महान नेताओं की यात्राओं के बड़े प्रोजेक्ट का काम पसंदीदा लोगों को देना और फिर उस पर अपने हिसाब से टिकट लगाकर जनता के बीच छोड़ देना, यही व्यवस्था है।

मैं मानती हूं। गुजरात के मोरबी पुल हादसा एक बेहद ही दुखद हादसा है। पुल के टूटने से लगभग 135 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद भी आज कई सवाल हैं जिन्हेंट देश जानना चाहता है। जिसका जवाब सरकार और प्रशासन दोनों को देना होगा। अगर वो बाँध इतना कमजोर था तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया, कैसे एक टाइम पर इतने लोग पुल पर चढ़ गए। तीसरा और अंतिम प्रशाशन ने उस पुल पर कोई नोटिस बोर्ड क्यों नहीं लगाया था। हादसे की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोरबी पहुंचकर हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। यह हादसा इतना बड़ा है कि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। वहीं हादसे के पीछे हुई लापरवाही का मामला भी सामने आया है। जिसने पुलिस और प्रशासन दोनों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। हादसे ने कुछ ऐसे सवालों को जन्म दे दिया है, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुल हादसे के बाद बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 09 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें पुल मैनेजर, 2 कॉन्ट्रेक्टर, 3 गार्ड, 3 टिकट क्लर्क शामिल हैं। इसी बीच मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का नाम लेकर उन्हें हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख भाई पटेल का नाम भी पुलिस एफआईआर में नहीं है। इस पुल के लिए कंपनी ने स्थानीय नागरिक निकाय से फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं लिया था। साथ ही इसे समय से पहले खोला गया। हादसे के वक्त पुल पर लोगों की संख्या भी ज्यादा थी। ऐसे में विपक्ष राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मोरबी हादसे में सरकार किसी को बचा रही है? कांग्रेस ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस घटना को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हों। बता दें कि मोरबी नगर निगम ने घड़ियां और ई–बाइक बनाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को इस पुल की मरम्मत का काम सौंपा था। मरम्मत के बाद पुल जब 26 अक्टूबर को जनता के लिए खोला गया तो उस वक्त ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने कहा था कि उनकी कंपनी ने मरम्मत पर दो करोड़ रुपये खर्च किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये पुल आराम से 8 से 10 साल तक चलेगा। अब मोरबी पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है।

विजया पाठक

भारत जोड़ो यात्रा

यात्रा से मंजिल मिलेगी जरूर

देश में फिर हुई नवीन क्राँति की शुरूआत

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश में नवीन क्रांति लाने के उद्देश्य से भारत जोड़ों यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा अपने पड़ाव का लगभग आधा समय पूरा कर चुकी है। कन्याकुमारी से निकली यात्रा ने धीरे-धीरे व्यापक रूप धारण कर लिया है। जन-जन से जुड़ाव करती हुई यात्रा सियासी माहौल को भी परिवर्तित करने लगी है। यह यात्रा कांग्रेस को भी मजबूती प्रदान कर रही है साथ ही देश की विपक्षी पार्टियों को भी एक सूत्र में बांधने में सफल होने लगी है। यात्रा का मकसद भले ही राजनीतिक न हो लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लगने लगा है कि यह यात्रा देश में एक बार फिर किसी बड़े परिवर्तन को लाने में कामयाब होगी। निश्चित ही यात्रा की सार्थकता और महत्ता ने देश की सत्तासीन पार्टी को चिंता में डाल दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता की परीक्षा होगी और देश के मिजाज का पता चलेगा। इतनी लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत करके वे शायद खुद की सहनशक्ति की भी परीक्षा ले रहे हैं। 07 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई उनकी इस यात्रा ने करीब आधा पड़ाव पूरा कर लिया है। इस यात्रा के मिल रहे परिणामों ने राहुल गांधी को निश्चित रूप से एक सहनशील और जिम्मेदार राजनेता के रूप में स्थापित किया है। यह यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि स्वयं राहुल गांधी के लिए भी अहम साबित हो सकती है। यात्रा के शुरुआती रुझान को देखें तो इसने कांग्रेस के कैडर में उत्साह भरने का काम किया है। सियासी गलियारों में कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिये अपने सोए हुए काडर को जगाते हुए पार्टी में एक नई जान फूंकना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। यात्रा के जरिये कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक नफरत फैलाने जैसे मुद्दों को उठाते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकने का काम कर रही है। हालांकि मीडिया में इस यात्रा का वह रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। जिसके कई कारण हो सकते हैं। वहीं देश के उदयोगपतियों की बात की जाए तो इतिहास की पदयात्राओं में उदयोगपति ऐसे यात्राओं में खुलकर साथ देते आए हैं लेकिन इस समय उदयोगपति देशहित से ज्यादा अपना हित साधने में लगे हैं। उन्हें देश से कुछ लेना देना नही है।

विजया पाठक

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी इस पदयात्रा को भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया है। इसी साल 07 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई उनकी यह यात्रा करीब 3,570 किमी का रास्ता तय करके 150 दिनों में जम्मू पहुंचेगी। वहीं इसका समापन होगा। यह यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि स्वयं राहुल गांधी के लिए भी अहम साबित हो सकती है। यात्रा के शुरुआती रुझान को देखें तो इसने कांग्रेस के कैडर में उत्साह

भारत जोड़ो यात्रा : क्या भारत में फिर

कांग्रेस पार्टी द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव के पहले जनसमर्थन जुटाने के लिये यह यात्रा शुरू की गई है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह रहे हैं- एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा। तब जुड़ेगा भारत। तब जुटेगा भारत। कुछ दिन में ही लगने लगा है कि इस यात्रा से और कुछ हो न हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर आने वाला है। यही सफलता के संकेत होते हैं। सफलता सत्ता की नहीं, जहां हैं, वहां से आगे बढ़ने की। आगे जरूर बढ़ा जा सकता है, अगर उत्साह है। उसकी दिशा सही है तो। बहरहाल, राहुल गांधी की यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो पार्टियां एक साथ आने की बात कर रही हैं, वे जुड़ भी रही हैं। एक-एक कर ही सही, एक-एक दिन उस यात्रा का हिस्सा सबको बनना चाहिए। सब विपक्षी पार्टियों को।

यह यात्रा भी होगी सफल- गांधी जी की यात्राओं को तो आज की राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आडवाणी की यात्रा, चंद्रशेखर की यात्रा, मुरली मनोहर जोशी की यात्रा को राजनीतिक रूप से सफल जरूर कहा जा सकता है। राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होगी, अभी से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि इससे कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में जोश जरूर आएगा। जो फिलहाल मायूस हैं। निराश भी। सही भी है। लगातार हार, अनवरत विफलता से मन टूट जाता है। कार्यकर्ताओं के टूटे हुए मन को जोड़ने का ही एक उपक्रम है यह भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैले कार्यकर्ताओं में अगर यह यात्रा उत्साह ला पाती है तो निश्चित ही यह कांग्रेस पर राहुल गांधी का उपकार होगा। अब तक जितनी भी हार के ठीकरे उनके सिर फोड़े गए हैं, सब के सब गायब हो जाएंगे। फिर कोई गुलाम नबी राहुल को कांग्रेस के पराभव का दोषी बताकर पार्टी नहीं छोड़ पाएगा।

दरअसल, यह यात्रा राहुल गांधी के उद्धार का उपक्रम कहा जाए तो भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

सभी पार्टियां बढ़ा रही मेलजोल- छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त मेल-जोल बढ़ा रही हैं। नीतीश कुमार सबसे मिल रहे हैं, लेकिन मिलने, बयान देने से काम नहीं होने वाला। भारतीय राजनीति में विपक्ष का सबसे बड़ा दुश्मन है छोटी-छोटी पार्टियों के नेताओं का बड़ा अहंकार। एक साथ

भरने का काम किया है। अतीत में हुई यात्राओं, चाहे वह लालकृष्ण आडवाणी की राम रथयात्रा हो या राज्य स्तरीय कई नेताओं की अपने-अपने राज्यों में निकाली गई यात्राएं, से प्राप्त राजनीतिक लाभांश के मद्देनजर कांग्रेसी भी इस यात्रा के कुछ सकारात्मक परिणाम अपने हक में देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि यह उत्साह चुनावी सफलताओं में परिणत कैसे

हो रही नवीन क्रांति की शुरूआत?

यात्रा में राहुल गांधी का बने रहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। जगह जगह उनके साथ समय बिता रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं। गले मिल रहे हैं। कहीं आश्वस्त कर रहे हैं तो कहीं हौसला अफजाई भी कर रहे हैं।

लोगों और मीडिया से करते हैं बात- कश्मीर से कन्याकुमारी के रास्ते में जब भी मौका मिल रहा है, राहुल गांधी मीडिया से भी बात कर रहे हैं। और हर किसी को अपने मन की बात भी बताते चल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात भी कह रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को भी संदेश दे रहे हैं और कांग्रेस समर्थक जनता को भी। केरल में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने एक व्यक्ति, एक पद को लेकर साफ कर दिया कि ये नियम हर किसी पर लागू होगा।

यदि गुजरात जाती यात्रा तो होता फायदा

अगर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को गुजरात की तरफ मोड़ लें तो निश्चित ही इस यात्रा का फायदा कांग्रेस पार्टी को वहां मिलेगा। अभी जहां कांग्रेस के पास लगभग 70 सीटें हैं। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के उन इलाकों से होकर गुजर जाये जहां कांग्रेस कमजोर है या जहां पिछली विधानसभा में हार मिली थी तो वहां कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हैं। इस तरह से गुजरात में कांग्रेस को चालीस से पचास सीट का फायदा हो सकता है। राहुल गांधी और उनकी टीम को यह सोचना होगा क्योंकि वर्तमान में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। इन प्रदेशों में अभी भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में हैं। यहां के कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने में यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। निश्चित ही इन दोनों प्रदेशों में यदि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव होता है तो कांग्रेस को मजबूती प्रदान होगी।

आना है, जुड़ना है, जीतना है तो छोटे-छोटे अड़ंगे हटाने होंगे। जैसे अटल जी ने हटाए थे। सबको साथ लेकर चले थे। हार्ड लाइन की पार्टी के नेता होकर भी सबको संभाला। सबकी सुनी। मानी भी। यही करना होता है। अपने दुखों को भीतर रखकर दूसरों के सुखों में सुखी होना पड़ता है। तब जीत होती है। तब विजय होती है।

यात्रा से पूरी तरह जुड़ गये हैं राहुल- राहुल गांधी को धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा में आनंद आने लगा है। अब तक

होगा, इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना देश को आजादी मिलने से बहुत पहले ही यानी ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ने ही राज किया है। पुरानी

क्या कांग्रेस की खोज है: भारत जोड़ो यात्रा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक परियोजना है। इससे एक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता की परीक्षा होगी और देश के मिजाज का पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह मार्च राष्ट्रीय ध्वज के मूल्यों के तले सभी भारतीयों को एकजुट करने की कोशिश है, जिसका मूल सिद्धांत विविधता है। मौजूदा सरकार में हिंदुत्व की विचारधारा के साये में यह मूल्य अब खतरे में है। हिंदुत्व के कटु एवं मुखर आलोचक और विविधता, संघवाद और उदारवाद के पैरोकार राहुल गांधी, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए अब तक अपनी सोच के साथ पर्याप्त जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। इस बीच हिंदुत्व की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हुई कि उसने दिल्ली फतह कर ली। हालांकि इसका भौगोलिक प्रसार अभी भी छितराया हुआ है। राहुल गांधी को इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है कि वे लगातार सक्रिय रहने की सीमित क्षमता रखने वाले मौसमी राजनेता हैं। इतनी लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत करके वे शायद खुद की सहनशक्ति की भी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी राजनीतिक यात्राओं ने इतिहास और यहां तक कि हाल में भी कई नेताओं की किस्मत लिखने और विचारधारा को उर्वर बनाने का काम किया है। महात्मा गांधी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक इस बात की मिसाल हैं। इसलिए राहुल गांधी को हर कदम पर उनके प्रशंसकों, आलोचकों और सबसे जरूरी तौर पर खुले विचारों वाले संशयवादियों द्वारा बारीकी से परखा जाएगा।

राहुल गांधी के लिए यह बहुत मायने रखता है कि अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले भारतीयों पर उनकी यात्रा का क्या असर पड़ता है। कांग्रेस ने मई महीने में उदयपुर में संपन्न मंथन सत्र में इस यात्रा की घोषणा की थी। पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उदयपुर में जो एलान हुए उन उपायों को आजमाए जाने पर ही यह यात्रा ज्यादा उपयोगी साबित होगी। भारत के तटस्थ लोगों की नाराजगी यह है कि सामान्य और प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं की कीमत पर परिवारवादियों ने कांग्रेस पार्टी के भीतर की सत्ता पर कब्जा कर रखा है। उदयपुर के सम्मेलन में पार्टी की अंदरुनी सत्ता में वंशवाद पर अंकुश लगाने का संकल्प लिया गया था। राहुल गांधी को इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता की पहचान करनी होगी और उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना होगा। यह धारणा गलत और भ्रामक है कि कांग्रेसी ढांचे से बाहर के गैर-सरकारी संगठन और अन्य सहयोगी उनकी राजनीति को उड़ान देंगे। राहुल गांधी को अवाम को यह समझाना होगा कि वह सत्ता बदलने पर देश को चलाने के काबिल हैं। साथ ही, उन्हें उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करना होगा जिन्हें लंबे समय से एक के बाद एक जड़विहीन लोगों के समूहों ने दबाकर रखा है। यह एक लंबी और कहें कि एकाकी यात्रा है।

कहावत है कि सत्ता में रहने का स्वाद आपको सड़क की हकीकत से बहुत दूर ले जाता है और दरबार छिन जाने के बाद ही ये अहसास होता है कि जनता से आखिर कैसे जुड़ा जाये। केन्द्र की सत्ता से हटने के आठ साल बाद कांग्रेस को पहली बार ये

13 दिन की यात्रा में मजबूत होगी मध्यप्रदेश कांग्रेस

20 नवम्बर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में प्रवेश करेगी। प्रदेश कांग्रेस द्वारा इस यात्रा की पुरजोर तैयांरियां की जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यात्रा को लेकर काफी गंभीरता दिखा रहे हैं। प्रतिदिन यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं और महत्वपूर्ण कार्यो की जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगले साल 2023 में मध्यप्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव है। इसलिए

अहसास हुआ है कि सरकार की नीतियों की मुखालफत करने के लिये सड़क पर उतरने के सिवा कोई और चारा नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद देश में प्रेम और

यह यात्रा खास मायने रखने वाली है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में यात्रा का काफी महत्व है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश में यात्रा का रूट भी आदिवासी क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस पहले से ही काफी मजबूत स्थिति में हैं। प्रदेश में यात्रा कुल 13 दिन रहेगी। इन 13 दिनों में मध्यप्रदेश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान होगी। हम कह सकते हैं कि यात्रा के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद भी होगा। वहीं प्रदेश बीजेपी में यात्रा को लेकर बैचेनी है। क्योंकि बीजेपी यह जानती है कि भारत जोड़ो यात्रा से राज्य में कांग्रेस के प्रति माहौल तो जरूर बनेगा और इस महौल का फायदा कांग्रेस को 2023 में मिलेगा। कांग्रेस भी यही चाहती है कि पार्टी के प्रति महौल बने।

दूसरी तरफ यात्रा को लेकर कमलनाथ काफी गंभीरता दिखा रहे हैं। हर एक बारीकी पर ध्यान देकर प्रयास कर रहे है कि प्रदेश में यात्रा सफल रहे। प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ताकि किसी भी प्रकार की कमीं न रहे। इससे पहले कमलनाथ दक्षिण में यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहां की सफलता को देखकर आए हैं। अब उनका यही प्रयास है कि प्रदेश में भी यात्रा प्रसिद्ध और कामयाब रहे।

उज्जैन में महाकाल लोक को अब कांग्रेस भी भुनाना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्यप्रदेश का रूट तय हो गया है और राहुल गांधी महाकाल मंदिर भी जाएंगे। उज्जैन में जनसभा भी होगी। नर्मदा पूजन के बाद राहुल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी जाएंगे। कांग्रेस का उजैन से हिंदू और महू से दलित-आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने का प्लान है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद अपनी निगरानी में पूरी योजना तैयार करवा रहे हैं।

20 नवंबर को आयेगी मप्र यात्रा- राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते 20 नवंबर को मध्यप्रदेश में एंट्री करेगी। प्रदेश में यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा के साथ पूर्व मंत्री सजन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, मुकेश नायक, अरुण यादव, महेंद्र जोशी, बाला बच्चन, रवि जोशी समेत करीब 10 नेता पूरे रूट का दौरा करेंगे। जिन जगहों पर यात्रा विश्राम करेगी, कांग्रेस नेता उन स्पॉट्स का निरीक्षण करेंगे। यात्रा में स्थानीय धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।

ट्राइबल बेल्ट में मैसेज देने की कोशिश- मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल की यात्रा जिस रूट से गुजरेगी, उसमें करीब 6 जिलों की 8 विधानसभाएं कवर होंगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी उज्जैन से बड़ा संदेश देंगे। यहां बड़ी जनसभा होगी। इसके लिए कमलनाथ ने पूर्व मंत्री सजन सिंह वर्मा को प्रभारी बनाया है। निमाड़, मालवा से होते हुए यात्रा राजस्थान की तरफ जाएगी, लेकिन मप्र के जिस इलाके से यात्रा गुजरेगी, उसे आदिवासी बहुल माना जाता है। लिहाजा यात्रा में भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने और आदिवासी सेनानायकों से जुड़े स्थानों पर जाने का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। उज्धैन से हिंदुत्व और महू से एससी, एसटी वोटर्स को साधने का संदेश दिया जाएगा।

इंदौर के बीचों-बीच से गुजरेगी यात्रा- यात्रा मप्र की धर्मनगरी उजैन और आर्थिक राजधानी इंदौर से गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा इंदौर शहर के बीचों बीच से गुजरेगी। इंदौर कांग्रेस के नेताओं ने सुझाव दिया है कि यात्रा राजबाड़ा से गुजरे। यहां अहिल्या बाई होल्कर की प्रतिमा पर राहुल माल्यार्पण करें। यहां मराठी वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। राजबाड़े पर राहुल की यात्रा गुजरने से शहरी वोटर्स से संवाद कराया जा सकता है। अलग-अलग श्रमिक वर्गो और व्यापारिक संगठनों के साथ राहुल मुलाकात कर सकते हैं।

भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है क्योंकि यह यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है। हालांकि सियासी गलियारों में कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रत्येक दिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्य व्यवस्था में लगे पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। कमलनाथ का प्रयास है कि यात्रा की सफलता के लिए किसी भी प्रकार की कमीं नहीं रहे।

भारत जोड़ो यात्रा का मध्यप्रदेश प्रभारी पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा को बनाया गया है। शर्मा सम्पूर्ण तैयारियों को लेकर काफी आश्वस्त हैं। उनका प्रयास है कि प्रदेश में यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाए।

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को भी यात्रा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा को लेकर पटवारी सक्रिय हैं और मिली जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं। जन-सहभागिता का दायित्व संभालते हुए पटवारी समय-समय पर बैठक कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।

लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिये अपने सोए हुए काडर को जगाते हुए पार्टी में एक नई जान फूंकना चाहती है।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। जगह-

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462 016 (म.प्र.)

दिनांक – 4 नवम्बर 2022

कमल नाथ
अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन

कार्यव्यवस्था आवंटन - भारत जोड़ो यात्रा

दिनांक 3 नवम्बर 2022 को मध्य कांग्रेस प्रभारी श्री जे पी अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में निम्न समिति के गठन किया जाता -

1. योजना एवं समन्वय – श्री सुरेश पचौरी
2. प्रशासन, सुरक्षा एवं पुलिस समन्वय – डॉ. गोविंद सिंह
3. स्वागत कार्यक्रम एवं बुरहानपुर, खंडवा एवं खरगोन यात्रा समन्वय – श्री अरुण यादव
4. उप-यात्रा समन्वय – श्री अजय सिंह राहुल
5. जन-सहभागिता (मोबिलाइज़ेशन), भोजन एवं महु कार्यक्रम समन्वय, – श्री जीतू पटवारी (प्रभारी),
6. महु कार्यक्रम - श्री प्रदीप अहीरवार(सह-प्रभारी)
7. इंदौर कंट्रोल रूम – श्री महेन्द्र जोशी
8. उज्जैन यात्रा एवं आम सभा समन्वय – श्रीमती शोभा ओझा, श्री सज्जन वर्मा एवं उज्जैन संभाग के समस्त विधायकगण
9. सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वय – श्री मुकेश नायक
10. लॉजिस्टिक व्यवस्था – श्री विशाल पटेल एवं श्री संजय शर्मा
11. भोजन व्यवस्था (भारत यात्री एवं विशेष अतिथि) – श्री संजय शुक्ला एवं श्री नीरज दीक्षित

दूरभाष - 0755-2551512, 2555452, फैक्स -0755-2577981

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462 016 (म.प्र.)

कमल नाथ
अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन

12. परिवहन समन्वय – श्री सुभाष सोजतीया एवं श्री निलय डागा
13. आवास व्यवस्था – श्री रवि जोशी एवं श्री बाल मुकुंद गौतम
14. वीआईपी यात्री, भारत यात्री एवं अतिथि यात्री समन्वय – श्री तरुण भनोट
15. नागरिक, सामाजिक संगठन एवं स्वयंसेवी संगठन समन्वय – श्री संदीप दीक्षित एवं सुश्री मीनाक्षी नटराजन
16. प्रचार प्रसार – श्री अशोक सिंह
17. ओंकारेश्वर दर्शन एवं नर्मदा आरती कार्यक्रम – श्री रवि जोशी एवं श्री राजनारायण सिंह पूरणी
18. शहीद टंट्या मामा जन्मस्थली कार्यक्रम – श्रीमती झूमा सोलंकी एवं डॉ. विक्रांत भूरिया

उपरोक्त के अतिरिक्त अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों को ज़िलावार ज़िम्मेदारी दी जाना है. राष्ट्रीय सचिव के द्वारा ज़िला स्तर पर टीम का गठन कर कार्य किया जाएगा. इस टीम के माध्यम से ऊपर वर्णित समितियों से समन्वय के साथ निम्न कार्य भी किया जा रहा है.

1. भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग की स्थानीय व्यवस्था
2. पानी, साफ़ – सफ़ाई, शौचालय, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ
3. स्वागत एवं स्थानीय जन सहभागिता
4. स्थानीय प्रचार – प्रसार
5. पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी, विभिन्न आनुषंगिक संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग से समन्वय एवं सहभगिता

(कमल नाथ)
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश कांग्रेस

दूरभाष - 0755-2551512, 2555452, फैक्स -0755-2577981

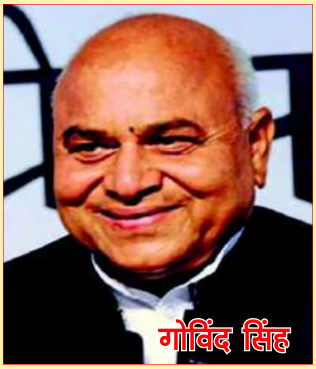
गोविंद सिंह

सज्जन सिंह वर्मा

अरूण यादव

शोभा ओझा

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह सभी वरिष्ठ नेता यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

जगह उनके साथ समय बिता रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं। हाथ मिला रहे है। गले मिल रहे है। कहीं आश्वस्त कर रहे है तो कहीं हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और बीच-बीच में मौका निकालकर कट्टर राजनीतिक विरोधी बीजेपी पर प्रहार भी

पदयात्राओं ने बदल दी भारत की सियासी तस्वीर

भारत में इससे पहले भी कई राजनीतिक पदयात्राएं निकाली गई हैं। इंदिरा गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी भी ऐसी राजनीतिक पदयात्राएं निकाल चुके हैं। इन यात्राओं का राजनीति में फायदा भी देखने को मिला। भारत में राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास काफी लम्बा है। असल में जब भी कोई पार्टी या कोई नेता चुनावी राजनीति में कमज़ोर होता है तो वो इस तरह की पदयात्राओं पर निकल पड़ता है। क्योंकि ऐसी यात्राओं में नेताओं का जनता से सीधा संवाद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। यानी आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वैसी पदयात्राएं पहली भी हमारे देश में हुई हैं और इनमें कुछ पदयात्राएं तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी द्वारा भी की गई थी। इमरजेंसी हटने के बाद जब वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थीं और ये कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने बिहार के बेलछी जाने का फैसला किया था। बेलछी की यात्रा से इदिरा गांधी को काफी फायदा हुआ और वर्ष 1980 में वो फिर से चुनाव जीत कर सरकार बनाने में सरकार रही।

महात्मा गांधी को जाता है पदयात्राओं की शुरुआत का श्रेय- लेकिन राजनीतिक पदयात्राओं की शुरुआत का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी राजनीतिक पदयात्राओं के Chief Architect थे। वैसे तो महात्मा गांधी अक्सर पैदल ही चला करते थे, जिससे आम लोगों से उनका सम्पर्क भी होता था और भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक जनचेतना भी जागती थी। महात्मा गांधी की ऐसी ही एक मशहूर पद यात्रा थी दांडी यात्रा, जिसकी शुरुआत उन्होंने साबरमती से की थी। तब उनके साथ सिर्फ 78 स्वयंसेवक थे और जब 386 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई, तब महात्मा गांधी के साथ सैकड़ों लोग जुड़ चुके थे। इस यात्रा का इतना बड़ा असर हुआ था कि एक वर्ष तक पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चलता रहा और इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बुनियाद पड़ी। राजीव गांधी, लालकृष्ण आडवाणी और चंद्रशेखर की यात्राओं ने भारत की तस्वीर बदल दी।

कर रहे हैं। रास्ते में जब भी मौका मिल रहा है, राहुल गांधी मीडिया से भी बात कर रहे हैं और हर किसी को अपने मन की बात भी बताते चल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात भी कह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का भी संदेश दे रहे हैं और कांग्रेस समर्थक जनता को भी

आजाद भारत की कई महत्वपूर्ण पदयात्राएं : बदल दी राजनेताओं की किस्मत

कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। माना जाता है कि बिखरती हुई कांग्रेस पार्टी को एकसूत्र में बांधने के इरादे से राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले हैं और पीएम मोदी के सामने तगड़ी चुनौती पेश करना चाहते हैं, क्या ऐसा हो पाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। आजाद भारत में इससे पहले भी देश में कई राजनीतिक यात्राएं हो चुकी हैं। उनका बड़ा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। आज़ाद भारत में इस तरह की यात्रा 1951 में आचार्य विनोबा भावे, 1982 में एनटी रामाराव की चैतन्य रथम यात्रा, 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, 2003 में वाईएसआर रेड्डी, 2013 में चंद्रबाबू नायडू, 2017 में दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा शामिल है। सिर्फ उत्तर और मध्य भारत ही नहीं दक्षिण भारत में भी यात्राओं का शानदार इतिहास रहा है। आंध्रप्रदेश की राजनीति में पदयात्रा का कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि वहां की राजनीति में सत्ता तक पहुंचाने का सबसे सटीक तरीका पदयात्रा को माना जाता है। आइये जानते हैं देश की कुछ राजनीति यात्राओं के बारे में-

सत्ता में रहते हुए शुरू हुई थी कांग्रेस संदेश यात्रा

1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस को रिकार्ड लोकसभा सीटें मिली थीं। 1985 में मुंबई (तब बाम्बे) में कांग्रेस के शताब्दी सत्र में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस संदेश यात्रा की घोषणा की थी। राजीव गांधी ने इस यात्रा का जिम्मा अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल को सौंपा था। राजीव गांधी ने यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर तत्कालीन कांग्रेस सेवा दल प्रमुख तारिक अनवर को पार्टी का झंडा सौंपा था। इस यात्रा की शुरुआत मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और उत्तर पूर्व के राज्यों से हुई थी और इसे तीन महीने के भीतर दिल्ली के रामलीला मैदान में समाप्त किया गया था। इस यात्रा ने सेवा दल और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे भारत को कवर करने के लिए प्रेरित किया।

सत्ता से हटने के बाद भी राजीव गांधी ने की थी यात्रा- वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली थी। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीती थीं और इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के संगठन और मजबूत करना था। इसे इतिहास में राजीव गांधी की रेल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तब राजीव गांधी यात्रा के दौरान ट्रेन की सेकेण्ड क्लास की बोगी में यात्रा करते थे। 1989 में चुनाव में हार मिलने के बाद राजीव गांधी ने साल 1990 में भारत यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नसीब नहीं हुई थी। उस दौरान राजीव गांधी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल भी उठने लगे थे। भारत यात्रा के जरिए राजीव गांधी आम लोगों के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन गुटबाजी की वजह से भारत यात्रा को सफल बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। उस दौरान कांग्रेस में कई क्षत्रप थे, जिन्होंने राज्य में यात्रा कर कांग्रेस को महत्वपूर्ण जीत दिलाई है इनमें वाईएसआर रेड्डी का नाम सबसे अहम है।

यात्रा में राहुल गांधी को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि यात्रा को लेकर बीजेपी चिंता में दिख रही है।

यात्रा लगभग पांच महीनों में 12 राज्यों

भारत यात्रा से चमकी चंन्द्रशेखर जी की सियासत

1983 में की गई चंद्रशेखर की भारत यात्रा की चर्चा आज भी होती है। युवा तुर्क के नाम से मशहूर और तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से भारत यात्रा शुरू की थी। चंद्रशेखर ने 06 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक कन्याकुमारी से राजघाट तक भारत यात्रा 4260 किलोमीटर की पूरी की थी। भारत यात्रा नाम से उनकी इस यात्रा को भी काफी तवजो मिली थी। यात्रा के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं, सामाजिक असमानताओं और जातिवाद की जड़ को खत्म करना शामिल था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जनमत तैयार करने में इस यात्रा ने बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। बाद में इस यात्रा ने चंद्रशेखर को 1990 में देश के प्रधानमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। इसी तरह की एक यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने भी की थी। ये बात वर्ष 1983 की है, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया था। इस यात्रा के ज़रिए वो देश के लोगों और उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे। ताकि वो राष्ट्रीय राजनीतिक के मंच पर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे सकें।

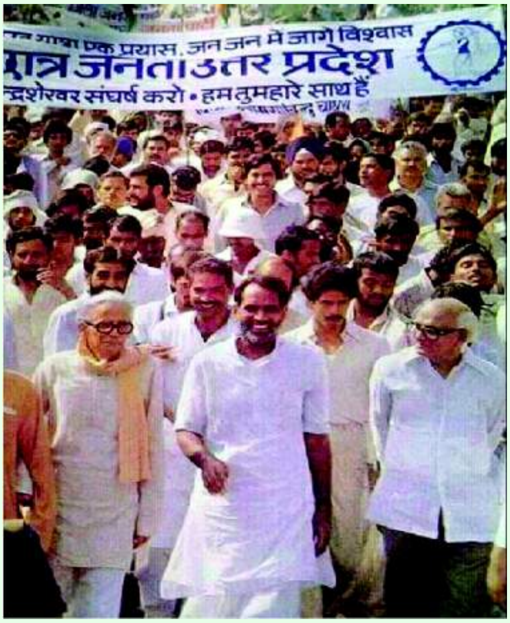

आडवाणी की रथयात्रा ने बदल दी राजनीति की दशा और दिशा

वर्ष 1990 में बीजेपी ने राम मन्दिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रथयात्रा की शुरुआत की थी, जिसका नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे। ये रथयात्रा गुजरात के सोमनाथ से उत्तरप्रदेश के अयोध्या तक प्रस्तावित थी। लेकिन उस समय बिहार में इस रथयात्रा को रोक दिया गया था और इसके पीछे कानून व्यवस्था को वजह बताया गया था। हालांकि इस रथयात्रा से तब बीजेपी को ज़बरदस्त फायदा हुआ और उसने 1989 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 1991 में 35 सीटें ज्यादा जीती और 120 सीटों के साथ कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के काल में 25

और दो केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी और इसके जरिये यात्रा महंगाई, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक नफरत फैलाने जैसे मुद्दों को उठाते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकने का काम करेगी। हम ये नहीं जानते कि इस पूरी

सितंबर 1990 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथयात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के जरिए भाजपा ने न केवल राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा उठाया बल्कि मंडल की राजनीति के खिलाफ कमंडल के दांव को आगे बढ़ाया। रथयात्रा के बीच राममंदिर आंदोलन में भारी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे। इस यात्रा ने मंदिर वही बनाएंगे जैसे नारों के बीच भाजपा की किस्मत के अलावा भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को काफी बदल दिया। इसने देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर पैदा की। इस यात्रा ने देश के राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। 1997 में आडवाणी ने 15,000 किमी की दूरी तय करने वाली स्वर्ण जयंती रथयात्रा में भी भाग लिया।

दिग्विजय की नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा से कांग्रेस की वापसी

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की साल 2017 की नर्मदा यात्रा पार्टी के लिए असरदार साबित हुई थी। 192 दिन की दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट पर समाप्त हुई थी। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना था। नर्मदा नदी के दोनों किनारे करीब 3,300 किलोमीटर की यात्रा दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ 6 महीने में पूरी की थी। 2018 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी साबित हुआ था। कांग्रेस 230 सीटों में 114 सीटों पर जीतने में कामयाब रही, वहीं भाजपा को 56 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। बाद में 2020 में मध्यप्रदेश में गुटबाजी की वजह से 22 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और सरकार अल्पमत में आने की वजह से सत्ता से दूर हो गई।

कवायद से कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों में कितना फायदा मिलेगा लेकिन एक स्वस्थ्य लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छी बात ये है कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का इतना तो अहसास हुआ कि वह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर

एनटी रामाराव की चैतन्य रथम यात्रा ने दिलाई सत्ता

स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के संस्थापक एनटीआर को रथ यात्रा का अग्रदूत माना जाता है। आंध्रप्रदेश में वर्ष 1982 में एनटी रामाराव ने चैतन्य रथम यात्रा निकाली। 75 हजार किलोमीटर लंबी इस यात्रा ने प्रदेश के चार चक्कर लगाए जो गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज है। एक वैन में बदलाव करके बने रथ में एनटीआर एक दिन में 100-100 जगहों पर रुकते। जनता इंतजार उनका करती थी, महिलाएं उनकी आरती उतारती थीं। यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव में तेलुगुदेशम पार्टी को 294 में से 199 सीटें मिलीं और एनटीआर आंध्रप्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यात्रा के दौरान अभिनेता से राजनेता बने एनटीआर ने सड़क किनारे होटलों में खाना खाया, अपने रथ में सोए।

नरेन्द्र मोदी की गुजरात गौरव यात्रा से हुई सत्ता वापसी

अपने पद से इस्तीफा देने और गुजरात विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से नौ महीने पहले भंग करने की सिफारिश करने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों के गौरव की अपील करने के लिए सितंबर 2002 में गुजरात गौरव यात्रा शुरू की थी। 2002 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने और मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के साथ यह यात्रा बड़ी सफल साबित हुई। राज्य में सांप्रदायिक दंगों के महीनों बाद दिसंबर में चुनाव हुए थे। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात में इसी तरह की यात्रा शुरू की और पार्टी विजयी हुई थी।

हुआ। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उसका पहला फर्ज यही बनता है कि वो आम जनता से जुड़ी तकलीफों को जानने-समझने के लिए पहले उनके बीच जाये और फिर सरकार पर सवालों की बौछार करे। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध की

वाईएसआर रेड्डी की आंन्ध्रप्रदेश यात्रा से मिली थी कामयाबी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वाईएसआर रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष तेलगु देशम पार्टी से लोहा लेने के लिए बनाया था। साल 2004 में वाईएसआर ने आंध्र प्रदेश में करीब 1600 किलोमीटर की पदयात्रा की और सत्ता पर काबिज हुए। वाईएसआर द्वारा किसानों और ग्रामीणों के लिए चलाई गई मुहिम शानदार तरीके से कामयाब हुई। यात्रा के दौरान वाईएसआर के चुनावी मुद्दों में मुफ्त बिजली और ऋण माफी शामिल थे, जो आम लोगों को आकर्षित करने के लिए थे। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को 27 लोकसभा सीटें जिताने और यूपीए की सरकार बनाने में कारगर साबित हुए थे। वाईएसआर 05 वर्षो तक सरकार चलाने में सफल रहे थे और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होने लगी थी। बाद में उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी उसी तर्ज पर आंध्र प्रदेश की यात्रा की थी और टीडीपी को हराकर सत्ता में आए थे।

वाम मोर्चा को हराने के लिए ममता बनर्जी की पदयात्रा

महात्मा गांधी की किताब से एक सबक लेते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जनता से जुड़ने के लिए 2011 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में कई बड़े पदयात्राएं निकालीं। यह उन कारणों में से एक था, जिसने टीएमसी को वाम मोर्चे को हराने में मदद की। इसने पश्चिम बंगाल में 33 साल बाद वाम मोर्चा को हराने में मदद की। इन यात्राओं से ममता बनर्जी को स्ट्रीट-फाइटर का खिताब हासिल किया। वर्ष 2007 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब नंदीग्राम की घटना के बाद ममता बनर्जी ने सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की थी और इसके चार वर्ष बाद 2011 में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थीं।

आवाज होना तो बेहद जरूरी है, वरना जनता तो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का फर्क ही भूल जाएगी। इसलिये बरसों पहले समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन सड़क खामोश हो जायेगी, उस दिन संसद आवारा

चन्द्रबाबू नायडू की वास्तुना मीकोसम पदयात्रा

इसी तरह वर्ष 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष में होते हुए 1700 किलोमीटर की यात्रा की थी और अगले साल 2014 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। साल 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा ने एन. चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी की पराजय में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसके बाद टीडीपी नेता नायडू ने भी साल 2013 में पदयात्रा की वही रणनीति अपनाई। उस समय 63 साल के हो चुके नायडू ने अप्रैल माह की भर गर्मी में वास्तुना मीकोसम (मैं आपके लिए आ रहा हूं) नाम से पदयात्रा शुरू की। करीब 208 दिनों में उन्होंने प्रदेश की करीब 2,800 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस यात्रा ने चंद्रबाबू नायडू को एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में स्थापित कर दिया। इस यात्रा के दौरान नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी ने जनता के बीच खोई हुई अपनी पकड़ को और पुरानी साख फिर से हासिल किया। नौ साल तक सत्ता से बाहर रहे। नायडू ने जून 2014 के विधानसभा चुनावों में 102 सीटों पर शानदार विजय प्राप्त की और वे फिर से मुख्यमंत्री बने।

जगन रेड्डी की प्रजा संकल्प यात्रा ने दिलाई सत्ता

आंध्र प्रदेश में 2017 में ही जगन मोहन रेड्डी ने भी 3400 किलोमीटर की यात्रा की थी और 2019 में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। वर्ष 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकाप्टर दुर्घटना में मौत के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद जगमोहन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाकर पिता की यात्रा निकाली जो उनके राजनीतिक करियर की खेवनहार बनी। 2014 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 6 नवंबर, 2017 को 3,648 किलोमीटर की पैदल यात्रा (प्रजा संकल्प यात्रा) शुरू की। यात्रा के दौरान आंध्रप्रदेश के लगभग सभी जिलों को कवर किया गया। 341 दिनों में वाईएसआरसीपी प्रमुख ने 100 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) शासन की विफलताओं को निशाना बना गया। रेड्डी हर दिन लगभग 15-30 किलोमीटर की यात्रा करते थे। महीनों बाद वाईएसआरसीपी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में 175 में से 151 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। जगहन मोहन रेड्डी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 में से 22 सीटों पर भी जीत हासिल की।

हो जायेगी। उनकी इस बात पर गहराई से गौर करें तो लगता है कि वे एक सांसद, नेता होने के अलावा काबिल दूरदृष्टा भी थे। बेशक पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ जनहित से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे उठाना

इंदिरा गांधी ने की थी बेलछी (बिहार) तक पदयात्रा

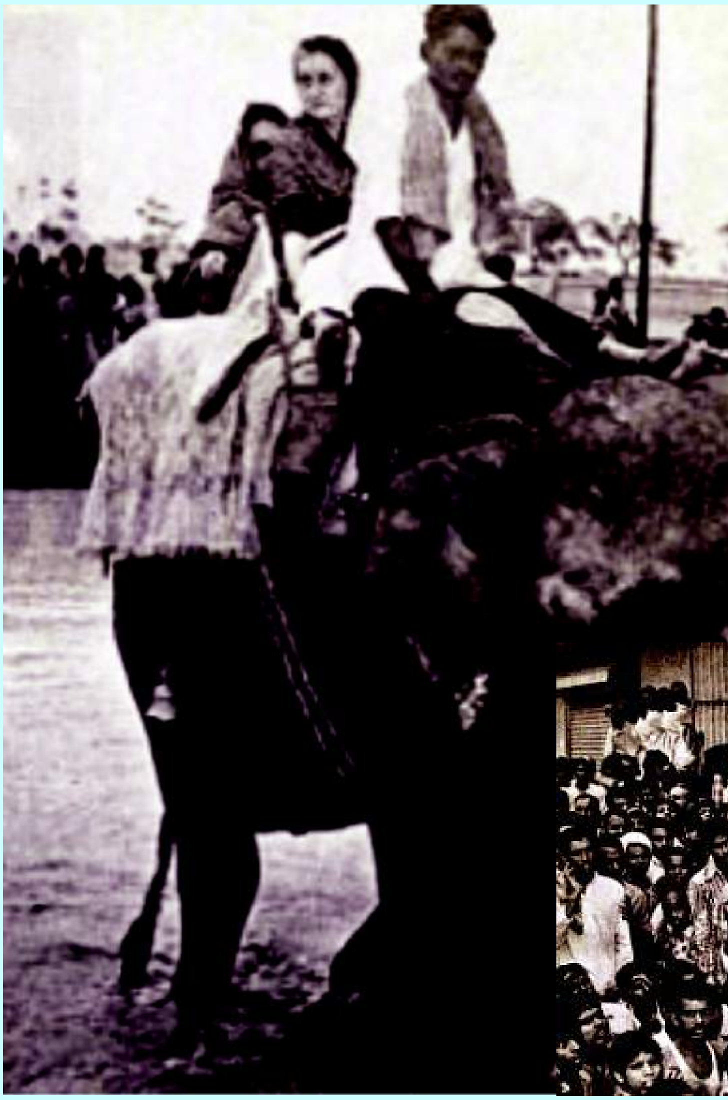

इमरजेंसी हटने के बाद जब सन 1977 के लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थीं और तब कहा जाने लगा था कि अब इंदिरा गांधी का राजनैतिक केरियर समाप्त हो जायेगा। तब इंदिरा गांधी ने बेलछी (बिहार) तक पदयात्रा करने का फैसला किया था। बेलछी की पदयात्रा का इंदिरा गांधी काफी फायदा हुआ और वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में वह भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहीं थी।

और उसके लिए जनता के बीच जाना, विपक्ष का भी हक है और सत्तारूढ़ पार्टी ये जुमला देकर उस जवाबदेही से बच नहीं सकती कि ये भारत जोड़ो नहीं, बल्कि परिवार बचाओ यात्रा है।

देश की राजनीति में कभी सबसे ताकतवर पार्टी रही और सबसे यादा सत्ता पर काबिज रह चुकी कांग्रेस पार्टी इस वक्त भारी अंतर्कलह और बिखराव से जूझ रही है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं खुद का अस्तित्व बचाना भी है। इस यात्रा से क्या कांग्रेस जोडो मकसद पूरा हो पाएगा? पार्टी के असंतुष्ट खेमे की नाराजगी दूर हो पाएगी? इसके अलावा विपक्षी दलों में खुद को साबित करने की चुनौती भी है।

भारत जोड़ो यात्रा : जन-जन से जुड़ाव

आप देखेंगे तो ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और नेता निकालते हैं, जो सत्ता से बाहर होते हैं और वो इन यात्राओं के ज़रिए वोटों की रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर की धार्मिक यात्रा है। ओडिशा और गुजरात की रथयात्रा है और श्रावण महीनों में शिवभक्त भी पद यात्रा निकालते हैं और ये पदयात्राएं धार्मिक होती हैं,

भारत जोड़ो यात्रा: सर्वधर्म समभाव

जिनका इतिहास काफी पुराना और प्राचीन है।

भारत जोड़ो यात्रा क्या है ?

भारत की सबसे पुरानी और बड़ी राजनितिक पार्टियों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरूआत की है।

उद्देश्य

कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा से उद्देश्य यही है कि वो धर्मनिरपेक्ष भावना के लिए देश के लोगों को आपस में जोड़ सके।

राहुल की यात्रा में राज्यों के

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो रोडमैप बनाया गया है, उसके तहत ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरेगी। हालांकि इस यात्रा में बिहार, बंगाल, उड़ीशा और झारखंड जैसे पूर्वी भारत के राज्यों और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यात्रा को ज्यादातर हिंदी बेल्ट वाले राज्य, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम माने जाते हैं से दूर क्यों रखा गया है? हालांकि पदयात्रा के रूट में पड़ने वाले राज्यों में कांग्रेस के पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन पर नजर डाले तो सहज ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कांग्रेस उन राज्यों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। जहां कांग्रेस ने या तो पिछले लोकसभा चुनावों या विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है। मसलन तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया था, कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनावों में जीते गए कुल 52 सीटों में से 23 इन्ही दो राज्यों से आये थे। साथ ही राहुल गांधी ने भी केरल के वायनाड से ही लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। आंध्रप्रदेश और और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां अधिकतर सीटों पर ऐसी पार्टियों का कब्ज़ा है जो ना तो खुलकर विपक्ष के साथ और ना ही कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस इन दो राज्यों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के साथ ही नए राजनैतिक सहयोगियों तलाशने की भी कोशिश में होगी। कांग्रेस के लिए इन चारों ही राज्यों को ज्यादा तवज्जो देने के पीछे यह भी बड़ा कारण हो सकता है कि इन चारों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब तक अपनी जड़ें नहीं जमा सकी है, साथ ही तेलंगाना छोड़ बाकि के तीन राज्यों में बीजेपी के लिए खाता

करोड़ों भारतीयों की आवाज बन सके और उसे बुलंद कर सके। इसके अलावा मौजूदा वक्त में देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, इसके बारे में वो जनता से बात कर सके। भारत जोड़ो यात्रा समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने हेतु शुरू की गई है। यात्रा के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है कि देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति अभियान छेड़कर लोगों को इन सभी समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाए। यात्रा के शुरू होते ही

चयन के पीछे का गणित

खोलना भी मुश्किल होता है। अभी हालांकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है मगर कर्नाटक में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में मजबूत दिख रही है, कई जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह को ठीक कर पाए तो पार्टी आगामी कर्नाटक चुनावों में भी बेहतर कर सकती है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है जहां कुछ समय पहले ही भाजपा और बागी शिवसैनिकों की सरकार बनी है, मगर इससे पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार में शामिल थी ऐसे में कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाहेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और पंजाब के रूप में उन राज्यों का चयन किया। जहां की जनता ने कांग्रेस नेतृत्व पर 2014 के ख़राब प्रदर्शन के बाद भी भरोसा दिखाया है। वर्तमान में राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही दो ऐसे राज्य हैं, जहां कांग्रेस अपने बलबूते सत्ता में कायम है, हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस ने 25 में से एक भी लोकसभा सीट जीत पाने में नाकाम रही थी। बावजूद इसके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश भी वो राज्य है जहां कांग्रेस में पिछले विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने में कामयाबी पायी थी हालांकि यह सरकार साल भर ही चल सकी, मगर बावजूद इसके यहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। पंजाब में अभी कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी और इस राज्य में कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है, ऐसे में इस यात्रा के जरिये कांग्रेस अपने काडर को मजबूत करने का प्रयास करेगी। हरियाणा में भी हुड्डा परिवार का अभी तक काफी दबदबा है और साथ ही मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में हैं तो कांग्रेस उनसे उपजे असंतोष को भी कैश करने का प्रयास करेगी।

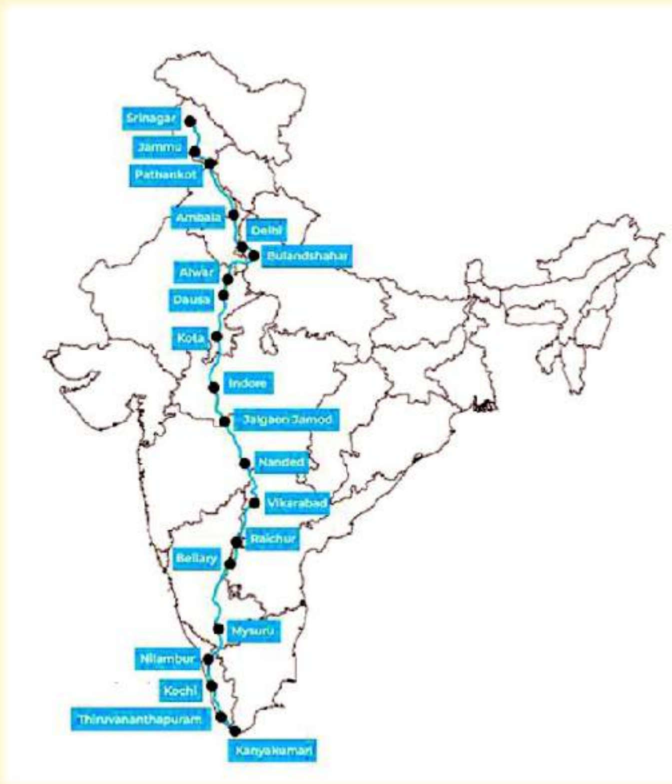

देश के लाखों लोग यात्रा से जुड़ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी, महंगाई, नफ़रत, विभाजन की राजनीति के विरुद्ध उठाती है। यात्रा सभी भारतीयों को मिलकर चलने हेतु आमंत्रित करती है और कहती है भारत देश हम सबका है। भारत जोड़ो यात्रा हम सबकी है।

राहुल गांधी ने कहा है कि ये यात्रा मेरे लिए तपस्या के समान है। कांग्रेस का इस यात्रा से यही उद्देश्य है कि वो धर्मनिरपेक्ष भावना के लिए देश के लोगों को आपस में जोड़ सके। करोड़ों भारतीयों की आवाज

जो माँ का सम्मान करते हैं वह देश का भी सम्मान करते हैं – राहुल गांधी एक संवेदनशील राजनेता हैं जिनमें सबके प्रति मान–सम्मान है। सहनशीलता है, गंभीरता है। एक राजनेता के वह सभी गुण विद्यमान हैं, जो नेतृत्वकर्ता में होते हैं।

बन सके और उसे बुलंद कर सके। इसके अलावा मौजूदा वक्त में देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, इसके बारे में जनता से बात करना। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस और राहुल गांधी की कोशिश ये है कि केंद्र सरकार, बीजेपी, एनडीए और पीएम मोदी के खिलाफ लामबंदी की जाए और कांग्रेस को देश की राजनीति में फिर पुराना मुकाम दिलाया जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यात्रा राहुल गांधी के लिए भी फुल टाइमर राजनीतिज्ञ बनने की अग्निपरीक्षा साबित होगी। राहुल गांधी जब से सियासत में आये हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है कि गंभीर मुद्दों पर भाषण करते हैं, बयान देते हैं और फिर किसी न किसी यात्रा पर निकल जाते हैं। राहुल को लेकर ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से तथ्यों के आधार पर सीधी लड़ाई लड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी ईमानदारी में किसी भी तरह से मोदी से कम नहीं हैं। देश में जो हालात हैं उसके हिसाब से निश्चित ही भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ी जरूरत है। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार जो राजनितिक हालात देश में बने हैं उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर सकती है। आजादी के 75 वर्ष बाद देश में जिस तरह से सामाजिक और धार्मिक आधार पर बंटवारा होने की बातें चल रही हैं या जातियों के बीच की खाई गहराने की खबरें आ रही हैं, उसमें बीजेपी हो या गैर-बीजेपी शासित राज्य, पूरे देश में सामाजिक समरसता टूटती सी लग रही है।

साथ ही लगता है जैसे लोगों के बीच भाईचारा कम हुआ है। अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा सामाजिक संगठनों की भारत जोड़ो यात्रा

देश में नया राजनीतिक जन जागरण बना सकती है जो 2024 में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वैसे ये कोई पहली यात्रा नहीं है। आज़ादी के पहले और बाद भी देश में बहुत यात्रायें हुई हैं। गांधी का दांडी मार्च आजादी दिलाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। आजकल हालात बीजेपी सरकार के खिलाफ बने हुए हैं लेकिन उस माहौल को बीजेपी के खिलाफ नेतृत्व देने वाला कोई बड़ा और अनुभवी नेता विपक्ष के पास नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार पर लगातार आक्रामक हैं। मोदी के खिलाफ अकेला नेता राहुल गांधी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसका फायदा राहुल गांधी नहीं उठा पा रहे हैं। सियासत में माना जाता है कि जो आरोपों की परवाह नहीं करते, जनभावनाओं के हिसाब से लगातार ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अवसर आने पर नेतृत्व उन्हीं के हाथों में होता है। बड़े राजनीतिक घराने में पैदा होना राहुल गांधी की गलती नहीं है और न ही उनको परिवारवाद के भाजपा के आरोपों से डरना चाहिए।

भारत जोड़ो यात्रा के पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के राम लीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों को उठाया वो सभी जनता से जुड़े हैं। महगाई, बेरोजगारी के साथ समाज में हो रहा बिखराव देश के सामने गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद कह चुके हैं कि सरकार बनाना आसान है लेकिन देश बनाना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि चुनाव जीता जा सकता है लेकिन देश चलाना चुनौतीपूर्ण होता है। दोनों के बयान चुनाव जीतने और देश को चलाने को लेकर हैं लेकिन मोदी और राहुल को लेकर जनता में परसेप्शन अलग अलग है। राहुल गांधी के प्रति परसेप्शन है कि वो ईमानदार हैं, सत्ता लोलुप नहीं हैं, मोदी सरकार के खिलाफ

राहुल गांधी में अपनत्व के गुण हैं :– एक परिपक्व राजनेता के गुण हैं कि वह अपनत्व की भावना पर कार्य करें। जिसमें भावना ऐसी हो, जो जुड़ने के लिए प्रेरित करे। यह आकर्षण राहुल गांधी में हैं।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कैसे निपटेगी भाजपा, राहुल के लिए इस यात्रा के क्या मायने?

भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कुछ सालों के अंदर उत्तर भारत में काफी अच्छा हुआ है। ऐसे में अब पार्टी का पूरा फोकस दक्षिण की तरफ है। इसके लिए पार्टी के दिग्गज नेता लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। राहुल की यात्रा से अगर कांग्रेस के साथ जनसमर्थन जुड़ता है तो इससे भाजपा की तैयारियों को झटका लग सकता है। भाजपा भी दक्षिण राज्यों को जीतना चाहती है। अभी दक्षिण के राज्यों में भाजपा काफी कमजोर है। भाजपा के नेता ये जानते हैं कि अगर राहुल की इस यात्रा का कुछ भी असर हुआ तो ये उनके लिए मुसीबत बन सकती है। यही कारण है कि राहुल की यात्रा का तोड़ निकालने की कोशिश शुरू हो गई है। राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस के लिए भी दक्षिण के राज्य कितने अहम हो सकते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस को सियासी जमीन बचानी है तो दक्षिण के राज्यों की मुख्य लड़ाई में बने रहना होगा। अभी ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ती रही है। फिर वह केरल हो या तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश। सभी जगह कांग्रेस मुख्य लड़ाई में रहती है। राहुल गांधी इसी को सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष कमजोर है देश में समस्याओं का अंबार है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जनता को जोड़ने में कितना सफल होती है ये राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जनता से सीधा संवाद करने में सफल रहे तो कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के खिलाफ उठने वाली आवाज दब जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार का वर्चस्व बने रहने पर भाजपा का कोई विरोध काम नहीं करेगा।

मजबूत बनाने की कोशिश में हैं। इसलिए उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा समय दक्षिण के राज्यों में दिया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली को भी छू लिया है। राहुल जानते हैं कि अगर इन राज्यों में वह कांग्रेस को मजबूत बना लेते हैं तो 2024 में भाजपा का परेशानी में डाल सकते हैं। वहीं, एकजुट हो रहे विपक्ष में भी कांग्रेस की अहमतियत बढ़ जाएगी। भाजपा ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया है। राहुल की इस यात्रा से जुड़ी छोटी सी छोटी बात पर भाजपा नेताओं का ध्यान है। राहुल कोई भी गलती करते हैं, तो उसे तुरंत सोशल मीडिया के जरिए वायरल करने की कोशिश की जा रही है।

अब तक कितने विवाद आ चुके सामने?

■ यात्रा की शुरुआत होते ही भाजपा ने सबसे पहले राहुल गांधी के कंटेनर को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। ये कंटेनर वो हैं, जिनमें राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता यात्रा के दौरान रूक रहे हैं। भाजपा ने दावा किया की ये कंटेनर बहुत आलीशान बनाए गए हैं। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और इन कंटेनरों के फोटो वीडियो जारी करके कहा कि कंटेनरों में केवल जरूरी सुविधाओं के अलावा कुछ नहीं है।

■ दूसरा विवाद राहुल के टी-शर्ट को लेकर उठा। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि राहुल गांधी करीब 42 हजार रुपये की टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने पलटवार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट और चश्मे का हवाला देते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब से घबरा गई है।

■ तीसरा विवाद राहुल गांधी की केरल के कैथोलिक पादरियों के साथ बैठक के बाद शुरू हुआ। इन पादरियों में विवादित पादरी जॉर्ज पोन्नैया भी मौजूद थे। इस बैठक की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इसमें राहुल गांधी पादरी से सवाल करते सुनाई दे रहे हैं कि क्या जीसस क्राइट (ईसा मसीह) ईश्वर का एक रूप हैं? क्या यह सही है? जवाब में पोन्नैया कहते हैं, हां वह असली भगवान हैं, शक्ति (हिंदू देवी) जैसे नहीं हैं।

राहुल गांधी पहले भी कर चुके है पदयात्राएं

करीब दो दशक के अपने राजनीतिक कॅरियर में राहुल गांधी कई पदयात्राएं कर चुके हैं। छोटी-छोटी भी और बड़ी भी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले भी वो किसान यात्रा पर निकले थे। उसके पहले भी किसानों की समस्याओं को करीब से समझने के लिए वो यात्राएं कर चुके हैं। खास बात ये रही कि वो यूपीए की सरकार में भी वैसे ही यात्राएं करते रहे, जैसे मौजूदा मोदी सरकार के जमाने में और लोगों पर

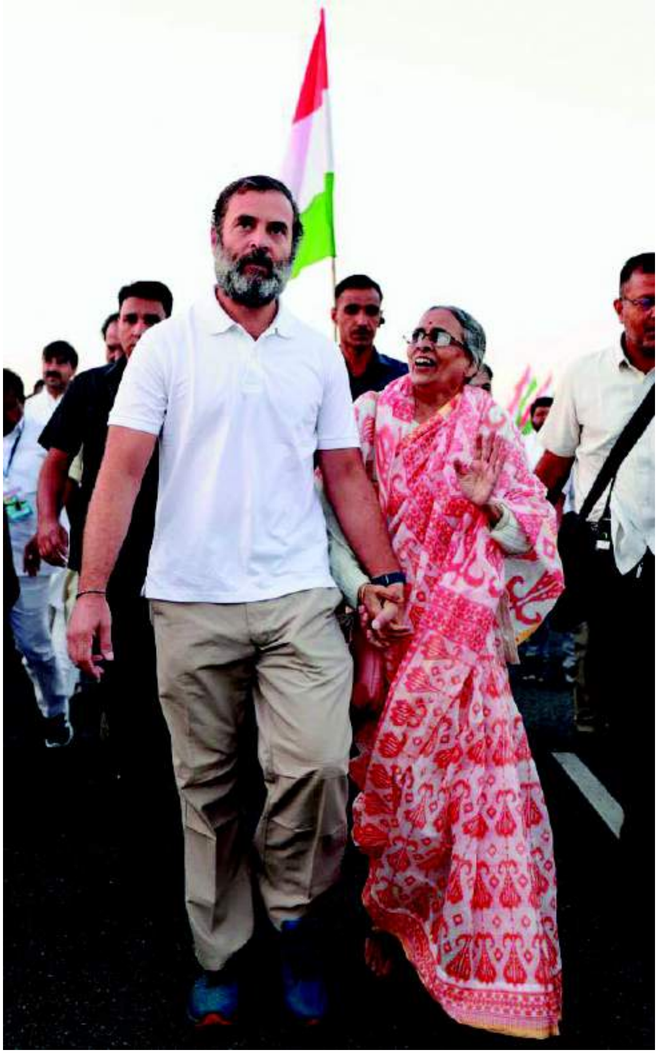

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सहभागी, महिला, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी बने हैं। यात्रा के पड़ाव के दौरान राहुल गांधी सभी से बड़ी ही आत्मीयता के साथ गले लगाकर मिल रहे हैं, जो सबको प्रभावित कर रहा है। यात्रा की यही सबसे बड़ी कामयाबी है, सफलता है।

असर नहीं छोड़ पाने की एक वजह ये भी लगती है। ये यात्रा भी 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की अलग तरीके की कोशिश ही है। ये समझाने के लिए कांग्रेस की तरफ से बार बार यही समझाया जा रहा कि यात्रा दलगत राजनीति से ऊपर है। कांग्रेस की तरफ से विपक्षी खेमे के ज्यादातर नेताओं से संपर्क किया गया है। कांग्रेस ये तो चाहती है कि

कांग्रेस का इतिहास कहता है कि ये पार्टी अपनी स्थापना के बाद कई बार टूटी है। लेकिन, हर बार उतनी ही मजबूती से खड़ी भी हुई है।

राज्यों के विपक्षी दल यात्रा में शामिल हों, लेकिन उसमें भी गांधी परिवार के परहेज सामने आ रहे हैं। ऐसा करने की एक वजह राज्य विशेष में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी है। 2021 में राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों में भी काफी मेहनत की थी और कांग्रेस नेताओं ने उनके स्वीमिंग स्किल से लेकर सिक्स पैक ऐब्स तक सब कुछ दिखाने की कोशिश भी

कांग्रेस तक नहीं सिमटी है भारत जोड़ो यात्रा

भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के दौरान ही परिकल्पना ये रही कि बीजेपी और उससे लगाव महसूस करने वालों को छोड़कर बाकी साथ आ सकें। विपक्षी दलों के नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। एहतियात भी बरते गये थे। तिरंगे के इस्तेमाल के पीछे भी मकसद यही रहा, कहीं कांग्रेस का झंडा देख कर विपक्षी दल बिदक न जायें। एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के जरिये विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को जारी रखने की भी पूरी कोशिश रही। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि राजनीतिक मकसद लेकर भी यात्रा का दायरा कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं रहने वाला है। दिग्विजय सिंह के समझाने का तो यही मतलब रहा कि यात्रा न सिर्फ लोगों को जोड़ने और लोगों से जुड़ने की कोशिश है, बल्कि संघ और बीजेपी के विरोध में खड़े राजनीतिक दलों के लिए विरोध का मंच भी है। राहुल गांधी भी पूरे रास्ते दोहराते रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों के बीच नफरत फैलाने वालों के खिलाफ यानी कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी बीजेपी के खिलाफ ही है।

खूब की थी। योगेंद्र यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। योगेंद्र यादव ने लिखा भी है, देश को एक पुल की जरूरत है। एक ऐसे राजनीतिक पुल की जो विपक्षी राजनीतिक दलों को जमीनी आंदोलनों से जोड़े। भारत के लोकतंत्र को फिर से जगाने-जिलाने और अपने गणराय को दोबारा हासिल करने की संभावना इसी राजनीतिक नवाचार पर निर्भर है। यहीं से निकलेगा देश का सच्चा प्रतिपक्ष। 2019 के आम चुनाव से पहले सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह ने ये मुहिम चलायी थी। मुहिम के तहत वो देश भर में घूम घूम कर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे थे जिनका समाज पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव देखा जाता हो। ऐसे लोगों से मिल कर बीजेपी नेता गुजारिश कर रहे थे कि वे लोगों को बीजेपी को वोट देने के फायदे समझायें और सुनिश्चित करें कि लोग बीजेपी को वोट दें। तब तो अमित शाह एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के घर तक पहुंच गये थे। राहुल गांधी नये सिरे से नेतृत्व के लिए तैयार हो गये हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व को लेकर। पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी की भागीदारी को लेकर असमंजस बना हुआ था।

क्या फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी कांग्रेस?

कांग्रेस का इतिहास कहता है कि ये पार्टी अपनी स्थापना के बाद कई बार टूटी है। लेकिन, हर बार उतनी ही मजबूती से खड़ी भी हुई है। हां, ये जरूर है कि इस बार

राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आदर्श स्वरूप महाराष्ट्र में दिखा पाएंगे क्या?

भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के ठीक दो महीने बाद यानी 07 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अपेक्षाकृत अच्छी रही, कम से कम विपक्षी खेमे की राजनीतिक सपोर्ट के हिसाब से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरंगा सौंप कर भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया था। डीएमके नेता एमके स्टालिन खुलकर भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट में खड़े देखे गये। वैसे भी पूरे देश में डीएमके ही ऐसी पार्टी है जो राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी का सरेआम समर्थन करती रही है। कांग्रेस के कुछ सहयोगी भी ऐसा करते हैं, लेकिन कई मौकों पर वे चुनाव जीतने के बाद इस मसले पर फैसला लिये जाने की बात करने लगते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथी विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से समर्थन मिलने की बातें राहुल गांधी को काफी राहत दे रही होंगी। शिवसेना में बगावत के बाद महाराष्ट्र में सत्ता बदल गयी और बीजेपी के सपोर्ट से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गये।

कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। सामने नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व और बीजेपी जैसी विशाल संसाधनों वाली राजनीतिक पार्टी है, ये नई बीजेपी है जो नए भारत का निर्माण कर रही है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में एक बड़ी भूमिका निभाई। आजादी के बाद 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 1977 तक देश पर केवल कांग्रेस का शासन था। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीन ली। हालांकि तीन साल के अंदर ही 1980 में कांग्रेस ने वापसी कर

भारत जोड़ो यात्रा ने 07 नवंबर को नांदेड़ से महाराष्ट्र में एंट्री की और अगले दो हफ्तों तक हिंगोली, वाशिम और बुलढाणा जिलों से होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शरद पवार भले ही अलग अलग छोर पर खड़े हैं, लेकिन दोनों की सोच एक जैसी ही है। दोनों के ही निशाने पर कांग्रेस रही है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में बर्बाद करने में दोनों में कोई उन्नीस-बीस नहीं लगता। और कांग्रेस के बाद अब उनके निशाने पर शिवसेना है। महाराष्ट्र में ढाई साल तक सरकार चला चुका विपक्षी गठबंधन भारत जोड़ो यात्रा में एक मंच पर नजर आएगा, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 2024 के आम चुनाव के ठीक बाद ही विधानसभा के लिए भी चुनाव होंगे और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का विपक्ष के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनना कोई कम महत्व वाली बात भी तो नहीं है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का असर तो देख लिया है, महाराष्ट्र में वैसे ही असर का इंतजार है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं तो क्या है कि कर्नाटक में बीजेपी ने जन-संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। बीजेपी की जन-संकल्प यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी अकेले नहीं कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की भी बीजेपी नेतृत्व ने ड्यूटी लगा दी है। येदियुरप्पा को हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, जिसे 2023 में होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में दक्षिण भारत में बीजेपी की पैठ बढ़ाने के मकसद से उठाया गया कदम माना जा रहा है।

सत्ता अपने नाम की। 1989 में कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1991, 2004, 2009 में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता हासिल की। आजादी के बाद से लेकर 2019 तक 17 आम चुनावों में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि 4 बार सत्तारुढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। कांग्रेस, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सर्वाधिक समय तक सत्ता में रही है। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थीं। देश की आजादी के संघर्ष से जुड़े

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमृतानंदमयी अम्मा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राहुल गांधी

सबसे मशहूर और जाने-माने लोग इसी कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी-नेहरू से लेकर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता कांग्रेस के ही सदस्य थे। इसमें कोई शक नहीं है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। जवाहरलाल नेहरु के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने पहले संसदीय चुनावों में शानदार सफलता पाई और ये सिलसिला 1967 तक चलता रहा। बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समाजवाद और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को सरकार का मुख्य आधार बनाया जो कांग्रेस पार्टी की पहचान बनी।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। पंडित नेहरु ने आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की थी। वो अक्सर इन उद्योगों को देश का आधुनिक मंदिर कहा करते थे। सत्ता में रहते हुए भी नेहरु ने हमेशा विपक्ष को मान-सम्मान दिया,विपक्षी नेताओं की वो बात सुनते थे। 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना मंजूर किया। अटल जी ने पंडित नेहरू से एक बार कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैंबरलिन भी है। लेकिन नेहरू उनकी बात का बुरा नहीं माने। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जबरदस्त रहा।

अटल जी ने पंडित नेहरू से एक बार कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैंबरलिन भी है। लेकिन नेहरू उनकी बात का बुरा नहीं माने। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जबरदस्त रहा।

बाद बने हैं। आजादी के बाद 75 में से 40 साल नेहरू-गांधी परिवार से ही पार्टी अध्यक्ष रहे जबकि 35 साल गैर नेहरू-गांधी परिवार ने कमान संभाली है। कांग्रेस पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता है। ये अलग बात है कि भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद फल-फूल रहा है।

पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली लेकिन फिर भी कितना धूमधाम से आजादी का 75वां दिवस मनाते हैं। बीजेपी जैसी विशाल संसाधनों वाली राजनीतिक पार्टी है। इसे हराने और खुद का वजूद बचाने के लिए कांग्रेस को इस बार कुछ नया करना होगा। ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। क्योंकि सत्ता-पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूत होने जरूरी हैं। एक पार्टी, एक नेता और एक संविधान चीन में ही अच्छा लगता है। भारत में नहीं।

पूर्वजों के परखे हुए मार्ग पर राहुल गांधी

रामायण में अन्याय का सामना करने के लिए राम ने पैदल चलने का मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध ने मनुष्य के दुख को

समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि – जिस दिन सड़क खामोश हो जायेगी, उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। उनकी इस बात पर गहराई से गौर करें तो लगता है कि वे एक सांसद, नेता होने के अलावा काबिल दूरदृष्टा भी थे।

लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस आम लोगों से दूर हो गई है। इतने सालों में देश की राजनीति भी बदली है। शासन का तरीका बदला है, इस दौर में कांग्रेस खुद को बदलने से फिलहाल चूकती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजनीति में कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। कांग्रेस के विरोधी कहते हैं कि कांग्रेस की जड़ें खत्म हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो अपनी जड़ों में ही झांके। कांग्रेस पार्टी की जड़ों पर नेहरु ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है। भला इतनी जल्दी ये जड़ें खोखली कैसे हो सकती हैं। 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी के अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से 18 अध्यक्ष आजादी के

पहचानने के लिए पैदल राह पकड़ी। आदि शंकराचार्य भारत की सनातन दृष्टि के अनुरूप जीवन की वीणा पर अद्वैत का स्वर साधने के लिए देश की चारों दिशाओं में पैदल चल पड़े। कवि रवीन्द्रनाथ टेगोर ने गीत गाकर कहा कि भले कोई साथ न हो, अकेले ही चल दो। महात्मा गांधी सबके हिस्से के स्वराज का एक मुट्ठी नमक उठाने

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए राहुल गांधी

> **देश को एक पुल की जरूरत है। एक ऐसे राजनीतिक पुल की जो विपक्षी राजनीतिक दलों को जमीनी आंदोलनों से जोड़े। भारत के लोकतंत्र को फिर से जगाने-जिलाने और अपने गणराज्य को दोबारा हासिल करने की संभावना इसी राजनीतिक नवाचार पर निर्भर है। यहीं से निकलेगा देश का सच्चा प्रतिपक्ष। - योगेन्द्र यादव, संस्थापक स्वराज इंडिया**

कुछ ही लोगों के साथ पैदल चल पड़े और कारवां बनता गया, बढ़ता गया। अन्याय की सत्ता कांपने लगी। अन्याय हमेशा अस्त्र-शस्त्र से लैस विशाल रथ पर सवार होकर चुनौती देता है। राम ऐसे ही रथ के सामने सैकड़ों मील पैदल चलते हुए पहुंचे। वे ज़मीन पर खड़े थे और अन्याय का सामना करने के लिए उनका आत्मबल से उवल शरीर ही रथ बन गया था। राम की देह के रथ के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि- शौर्य और धैर्य ही इस रथ के दो पहिए हैं। सत्याग्रह और सदाचार उस पर लहराती मजबूत ध्वजा-पताका हैं। शक्ति, समझदारी, संयम और परोपकार ही इस रथ के घोड़े हैं जो दया, क्षमा और समता की डोर से जुड़े हैं। प्रार्थना ही इस रथ की सारथी है। त्याग ही उसकी ढाल और संतोष तलवार है। श्रेष्ठ विज्ञान ही धनुष है। सद्भाव से संचित बुद्धि ही प्रचण्ड शक्ति है और निर्मल मन ही वह तरकस है जिसमें सबके बहुरंगी विश्वासों के बाण भरे हैं। ऐसा धर्ममय शरीर रूपी रथ जिसके पास हो वह सबके बहुरंगी विश्वासों की एकता के बाण चलाकर अन्याय का सामना करने में इतना समर्थ हो जाता है कि कोई अन्यायी उसे परास्त नहीं कर सकता। महात्मा गांधी के पास इसी परखे हुए रथ का एकमात्र विकल्प था। वे चम्पारण से नोआखाली तक असहाय और पराधीन होते जाते लोगों के पास पैदल चलकर गये। उनके मन में केवल यही भाव था कि लोगों के बीच जाकर उनकी पीड़ा को जानो और

भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव ऐसा रहा कि दिव्यांग जन भी यात्रा में सम्मिलित हुए और राहुल गांधी के सहयोगी बने।

उन्हें इस पीड़ा के पैदा होने का सच बताओ- गो टु द पीपुल, टेल द ट्रुथ। फिर लोग अपना रास्ता ख़ुद निकाल लेंगे। अन्याय साधुवेश में सत्ता का अपहरण करने आता रहा है। जीवन को बहुरूपिए ही ठगते रहते हैं। स्वराय के सत्याग्रह की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने अपने लिए उस असहाय जीवन के वस्त्र चुनें जो वह पहनता है। सत्य का साक्षात्कार गैर बराबरी में संभव नहीं। उसे तो परस्पर समता और सहयोग की चौपाल चाहिए।

निश्चित ही भारत जोड़ो यात्रा जैसी पदयात्राएं एक लोकतांत्रिक देश में नवीन क्रांतियों की शुरूआत करती है, जो न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। बल्कि सत्तासीन सरकारों को सचेत करने के लिए भी प्रेरित करती है। राहुल गांधी आज जिस उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं, वह देश के हित में हैं, लोकतंत्र के हित में हैं। साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी के भी हित में हैं। खासकर भारत जैसे देश में तो इन पदयात्राओं का खासा महत्व रहा है, जो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने में सटीक होती हे। मेरा मानना है कि यह यात्रा निश्चित ही आने वाले समय में कोई राजनीतिक परिवर्तन लायेगी।

राजस्थान में बीजेपी को वसुंधरा राजे सिंधिया को संभालने की चुनौती

राजस्थान भाजपा में सबसे अधिक बिखराव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण हो रहा है! वसुंधरा राजे पूरा प्रयास कर रही है कि उन्हें एक बार फिर नेता प्रोजेक्ट कर प्रदेश की कमान सौंप दी जाएं। मगर भाजपा आलाकमान ऐसा करना नहीं चाहता है। भाजपा आलाकमान के बार-बार चेताने के बावजूद राजस्थान के भाजपा नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में भाजपा संगठन को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस को हरा पाना मुश्किल है। इसीलिए नड्डा स्वयं भी राजस्थान के दौरे कर रहें है और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी लगातार राजस्थान भेज रहे हैं। ताकि राजस्थान में नेताओं के आपसी मतभेद समाप्त हो सके। मगर नड्डा के प्रयास कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान के संगठन में सबसे अधिक बिखराव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण हो रहा है। वसुंधरा राजे पूरा प्रयास कर रही है कि उन्हें एक बार फिर नेता प्रोजेक्ट कर प्रदेश की कमान सौंप दी जाएं। मगर भाजपा आलाकमान ऐसा करना नहीं चाहता है। भाजपा आलाकमान का मानना है कि प्रदेश में अब वसुंधरा राजे पहले की तरह लोकप्रिय नहीं है। इसीलिए पार्टी नए नेतृत्व को तैयार कर रही है। जो आने वाले समय में पार्टी की कमान संभाल सके। हालांकि वसुंधरा राजे अपने पक्ष में तर्क देती है कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने प्रदेश में दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मगर उनके विरोधियों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा को दोनों ही बार चुनाव में मात भी खानी पड़ी थी। माना जा रहा है कि अगर राजस्थान भाजपा की हालत ख़राब है तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह वसुंधरा राजे भी हैं। यदि वह लोकप्रिय नेता होती तो उनके मुख्यमंत्री रहते पार्टी चुनाव क्यों हारती। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ही राजस्थान में पार्टी की एक छत्र नेता थी। मगर फिर भी पार्टी चुनाव हार गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में तो राजस्थान में भाजपा 163 सीटों से घटकर मात्र 73 सीटों पर आ गई थी। भाजपा को सीधे-सीधे 90 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। वसुंधरा सरकार की नाकामियों को भुनाकर कांग्रेस ने घर बैठे सत्ता हथिया ली थी। अपने मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल में वसुंधरा राजे पर उनकी पार्टी के ही नेता चाटूकारों से घिरे रहने का आरोप लगाते हैं।

वसुंधरा राजे की कार्यशैली से राष्ट्रीय

स्वयं संघ के पदाधिकारी भी नाराज रहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार वसुंधरा सरकार को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी भी दी थी। मगर वसुंधरा राजे ने किसी की एक नहीं सुनी थी। जिसके परिणामस्वरुप ही राजस्थान में भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री यूनुस खान, कालीचरण सर्राफ, राजपाल सिंह शेखावत, प्रताप सिंह सिंघवी, भवानी सिंह राजावत, उनके विशेषाधिकारी धीरेन्द्र कमठान जैसे लोग सत्ता के केंद्र बन गए थे। जिनकी सलाह पर ही वसुंधरा राजे फैसले लिया करती थी। वसुंधरा राजे आज भी अपनी उसी पुरानी चैकड़ी से घिरी नजर आती है। भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा वसुंधरा के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जिसका पार्टी संगठन की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराया जाता है। मगर फिर भी वसुंधरा राजे अपनी चैकड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा विरोधी खेमे के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सांसद किरोडी लाल मीणा, ओम माथुर, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी जैसे नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने पर पार्टी में किसी एक नेता की छाप नहीं होगी। इससे प्रदेश के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जिसके नतीजे भी सकारात्मक होने की आशा की जा सकती है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में बढ़ती कलह को मिटाने के लिये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस बैठक में राजस्थान के नेताओं की जमकर क्लास ली।

सूत्रों के मुताबिक नड्डा और शाह ने पार्टी नेताओं को दो टूक शब्दों में कहा कि आपसी लड़ाई और टांग खिंचाई छोड़कर गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ो। 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक साल का समय बचा है। हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बड़े नेताओं द्वारा प्रदेश में अलग-अलग दौरे और यात्राएं की जा रही हैं। हमारे पास सभी की रिपोर्ट है। इसलिए फिर से समझाया जा रहा है कि पार्टी अनुशासन में रहकर एकजुटता से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। प्रदेश में बीजेपी के आंदोलनों और कार्यक्रमों में सभी नेताओं की उपस्थिति अनिवार्य हो। अगर उपस्थित नहीं हो सकते तो पहले ही उचित कारण के साथ पार्टी को सूचना दी जाए। आगे से राजस्थान बीजेपी के सभी सीनियर नेता प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लें। खबर है कि राजस्थान कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी नेतृत्व ने राजस्थान के नेताओं को साफ संदेश दिया है कि व्यक्तिगत एजेंडे को नहीं, पार्टी के एजेंडे को लेकर सभी मिलकर आगे बढ़ें। राजस्थान में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करना है तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को पहले सूचना देकर और मंजूरी लेवें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ेगी। राजस्थान के नेता किसी भी कार्यक्रम को करने की मंजूरी संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी महासचिव से लें। बताया जाता है कि अमित शाह के साथ ही बीएल संतोष ने भी जमकर नेताओं की खिंचाई की थी। बैठक में राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने का ज्ञापन देने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के घर गए बीजेपी नेताओं द्वारा वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने के बाद बढ़े विवाद पर भी पार्टी नेतृत्व द्धारा चर्चा की गयी।

राजस्थान में बीजेपी नेताओं की एकला चलो की नीति और देवदर्शन, धार्मिक यात्रा के नाम पर खुद का स्वागत, अभिनंदन

कार्यक्रम करवाने और जगह-जगह जन सभाएं करने की शिकायत पार्टी आलाकमान तक पहुंची है। प्रदेश में पार्टी को सूचना दिए बिना इस तरह की यात्राएं करने पर भाजपा संगठन में नाराजगी है। पार्टी के पहले से निर्धारित कार्यक्रमों मे भी सीनियर नेता नहीं पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को एकजुट होने की बार-बार नसीहत देने के बावजूद गुटबाजी और अंदरुनी कलह बार-बार उजागर हो रही है। ऐसे में पार्टी की मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने के लिये भाजपा आलाकमान को ही मैदान में उतरना होगा।

मोरबी पुल हादसा...

लापरवाही का जिम्मेदार कौन?

किसके हाथ खून से रंगे? गुजरात मॉडल में मौत का सौदागर कौन?

गुजरात के मोरबी शहर में पुल हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? सैंकड़ों परिवारों के उजड़ने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ढह गए इस पुल के मरम्मतकर्ता ने दोबारा खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था। न ही इसे खोलने के लिए सरकार से अनुमति ली गई। पुल हादसे में लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है। पुल गिरने के बाद सवाल केवल एक ही है कि आखिर यह पुल गिरा कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

विजया पाठक

गुजरात के मोरबी शहर में पुल हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? सैंकड़ों परिवारों के उजड़ने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ढह गए इस पुल के मरम्मतकर्ता ने दोबारा खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था। न ही इसे खोलने के लिए सरकार से अनुमति ली गई। पुल हादसे में लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है। पुल गिरने के बाद सवाल केवल एक ही है कि आखिर यह पुल गिरा कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ओरेवा नाम की एक प्राइवेट ट्रस्ट ने सरकार का टेंडर मिलने के बाद पुल का रेनोवेशन कराया। मरम्मत के लिए सात महीने से पुल बंद था, जिसे 26 अक्टूबर 2022 को खोला गया। लापरवाही का जिम्मेदार कौन? पुल दोबारा

143 साल बाद टूटा मोरबी पुल, इस पुल से ये राजा दरबार जाते थे, आज लोगों की कब्रगाह बना

गुजरात के मोरबी पुल अब से करीब 143 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बना था। उस समय इस पुल से मोरबी के राजा प्रजावत्सल सर वाघजी ठाकोर राज महल से राज दरबार तक जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। राजशाही खत्म होने के बाद इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई थी। उस समय से लेकर अब तक नगर पालिका के पास ही पुल की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ही थी कि पुल के मेंटिनेंस कार्य के लिए उसे करीब 6 मीहने के लिए बंद किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई भी पुल पर अपनी मर्जी से जा सकता है। बल्कि इसके लिए बकायदा टिकट लेनी पड़ती है और उसके बाद कोई पुल पर जाता है। मच्छु नदी पर मोरबी पुल बना है। लकड़ी और तारों के सहारे बना करीब 765 फीट लंबा ये पुल मोरबी में बना है। गुजरात के मोरबी में बना अंग्रेजों के जमाने का बना पुल ऐतिहासिक धरोहर है। जिसका उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेंपल ने किया था। उस समय पुल को बनाने का सारा सामान इंग्लैंड से लाया गया था। इस पर करीब साढ़े 3 लाख रुपये का खर्च हुआ था।

खोलने से पहले न कोई सर्टिफिकेट, न सरकार की अनुमति...। जिस कंपनी को इस पुल के रखरखाव का काम सौंपा गया है उसका नाम ओरेवा है, जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों, दिवाल घड़ियों और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। एक बल्ब बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत और उसके रखरखाव का काम क्यों दिया गया, ये समझ से परे है। इस बीच इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की याद दिला रहे हैं, जो उन्होंने साल 2016 में कोलकाता फ्लाईओवर हादसे के बाद दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का पुराना वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी का एक वीडियो साझा किया, जब 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक पुल गिर गया था। पीएम ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था- यह भगवान की ओर से एक संकेत है कि किस तरह की सरकार चलाई गई। मोदी

जिस कंपनी को इस पुल के रखरखाव का काम सौंपा गया है उसका नाम ओरेवा है, जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों, दिवाल घड़ियों और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। एक बल्ब बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत और उसके रखरखाव का काम क्यों दिया गया, ये समझ से परे है।

मोरबी घटना पर 06 बड़े सवाल

● बगैर सर्टिफिकेट क्यों खुला पुल?

पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया गया था। पुल मोरबी नगरपालिका की संपत्ति है, लेकिन 15 सालों तक रखरखाव और संचालन के लिए इसे कुछ महीनों पहले ओरेवा ग्रुप को सौंपा था। हालांकि निजी कंपनी ने जानकारी दिए पुल आने वालों के लिए खोल दिया था। इसके चलते हम पुल का सेफ्टी ऑडिट नहीं करा सके।

● खोला झूलता पुल

रिनोवेशन के काम के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया था लेकिन स्थानीय नगरपालिका ने अब तक कोई फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। अब सवाल उठता है कि आखिर बगैर सर्टिफिकेट पुल को आम जनता के लिए कैसे खोल दिया गया। लापरवाही या फिर संयोग?

● जिम्मेदार कौन?

मार्च 2022 में मोरबी की ओरेवा ग्रुप (अजंता मेन्युफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड) को पुल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिलहाल, कंपनी के खिलाफ स्नढ्ढ दर्ज कर ली गई है। हालांकि, इसके बाद भी टिकट बिक्री, नगरपालिका की भूमिका समेत कई सवाल बने हुए हैं। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि जिम्मेदारी किसकी है।

● रिनोवेशन हुआ तो हादसा क्यों हुआ?

पुल को करीब 7 महीने पहले रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। अब सवाल है कि रिनोवेशन के बाद भी यह हादसा कैसे हो गया। कुछ दिन पूर्व ही रिनोवेशन के बाद खुला पुल किन परिस्थितियों में और कैसे गिर गया।

● क्षमता से ज्यादा लोगों को पुल पर जाने क्यों दिया?

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुल की सैर करने वाले लोग टिकट लेकर गए थे। इससे साफ है कि पुल की क्षमता और लोगों की गिनती के बारे में टिकट बेचने वाले को जानकारी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पर्यटकों से तय से ज्यादा राशि भी वसूली जा रही थी।

● भीड़ को क्यों नहीं किया गया नियंत्रित?

पुल काफी ज्यादा पुराना है, जिसकी क्षमता करीब 100 लोगों की है, लेकिन हादसे के वक्त उस पर 250 से ज्यादा लोग थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा कि जब प्रशासन को पुल की क्षमता की पूरी जानकारी थी, तो वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं? पुल काफी जर्जर हो चुका था, जिसके बाद एक निजी कंपनी को इसका टेंडर दिया गया। जिसने 07 महीने पहले पुल की मरम्मत की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी क्यों नहीं समझा? ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये हादसा था या फिर साजिश? टिकट बेचने का इंतजाम, लेकिन सुरक्षा पर नहीं दिया ध्यान पुल इलाके का एक पिकनिक स्पॉट बन गया था। जिसको देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहां पर कुछ कर्मचारी मौजूद थे, जो टिकट बेच रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक कर्मचारियों का पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा टिकट बेच मुनाफा कमाने का था, जिस वजह से भीड़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है, जब प्रशासन को भीड़ के बारे में पता था तो वहां पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की गई?

की इसी बात को लेकर श्रीनिवास ने कहा- क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी हादसे के बाद प्रधानमंत्री के उस बयान की याद दिलाई थी। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर राजनीति करने की बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे राहत व बचाव कार्य में लगें।

यहां सिर्फ पुल नहीं टूटा है। यहां टूटी हैं जिंदगियां, यहां टूटी हैं उम्मीदें, टूटी हैं सांसों की डोर और टूटी है मानवता। गद्दी पर बैठे धृतराष्ट्रों से अब चीखती पुकारें यही पूछ रही हैं कि अंग्रेजों की गुलामी के जंजीर तोड़ रहे हो, शहरों और सड़कों के नाम बदल रहे हो, स्टेशनों के नाम बदल रहे हो तो फिर 100 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए इस मौत के झूले को क्यों नहीं बदला? हादसे और 150 लोगों की जान लेने के बाद सिस्टम की कुंभकरणी नींद टूटी है। रिएक्शन आ रहे हैं, एक्शन हो रहा है। आरोप ट्रांसफर किए जा रहे हैं लेकिन कुछ बुनियादी सवाल पूछेंगे तो पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। बस दोषियों को पकड़ कर ऐसी

सजा देनी बाकी रह जाएगी कि एक नजीर बन जाए। लेकिन मिलेगी ऐसी सजा? या भ्रष्टाचार की डकार की आवाज में माताओं-बहनों-बेटों-बेटियों-पिताओं की हृदयविदारक चीखें गुम हो जाएंगी। भारत में विकास के लिहाज से कथित सिरमौर राज्य, बहुप्रचारित गुजरात मॉडल वाले राज्य... में बने इस पुल को गुजराती अंग्रेजों के जमाने से झेल रहे थे, लेकिन पुल और नहीं झेल सकता था। 30 अक्टूबर को आखिर ये पुल अपनी उम्र और बीमारी और नहीं झेल पाया। वो पहले से ही कराह रहा था। कह रहा था थक गया हूं, मुझे रिटायर करो, लेकिन गुजरात के बड़बोले नेता अपने बड़बोलेपन में मशगूल थे। उन्होंने उसे रिटायर नहीं किया, रिपेयर किया। अभी चंद दिनों पहले ही मरम्मत के बाद गुजराती नव वर्ष के मौके पर चालू किया गया था।

अगर, रिनोवेशन के बाद भी ये इतनी जिंदगियों को लील गया, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसने लगाया सैकड़ों जिंदगियों पर दांव, किसके हाथ खून से रंगे? मोरबी पालिका कह रही है कि रखरखाव करने वाली कंपनी ओरेबा ने पुल को बिना मंजूरी के खोल दिया। सवाल ये है कि मोरबी ब्रिज बिन मंजूरी खुला तो क्यों आंख मूंदे रही पालिका? ये कोई छोटा पैकेट नहीं, पुल था, किसी के निजी कमरे में नहीं खुला था। बड़ा पुल था, शहर के बीच में था। पुल खुले चार-पांच दिन हो चुके थे। नजर नहीं आया क्या? क्यों नजर नहीं आया? सिक्कों की चमक से आंखें चुंधिया गई थीं या चुनावी सीजन में नेताओं की धमक से आंखें बंद कर ली थी? इस देश में गलियों की तख्ती तक का लोकापर्ण करने नेता आ धमकते हैं, यहां किसने किया था?

इसी मोरबी में 1979 में एक बांध टूटा था। 1500 लोग मरे थे। तब आरोप लगा था कि इंदिरा गांधी ने लाशों से आती दुर्गंध से बचने के लिए नाक बंद कर ली थी। अब सवाल पूछा जाएगा गुजरात और मोरबी के नेताओं ने क्यों इतनी बड़ी आपराधिक लापरवाही पर चार पांच दिनों तक आंख बंद कर ली?

इसी मोरबी में 1979 में एक बांध टूटा था। 1500 लोग मरे थे। तब आरोप लगा था कि इंदिरा गांधी ने लाशों से आती दुर्गंध से बचने के लिए नाक बंद कर ली थी। अब सवाल पूछा जाएगा गुजरात और मोरबी के नेताओं ने क्यों इतनी बड़ी आपराधिक लापरवाही पर चार पांच दिनों तक आंख बंद कर ली? कांग्रेस पूछ रही है कि क्या चुनावी माइलेज लेने के लिए हड़बड़ी में

ब्रिज को खोला गया? क्या ये सच है? क्या वोट के लिए गुजरातियों की जिंदगी से सियासी खेल खेला गया? बताना होगा। इस मौत के झूले पर बड़ी जिंदगी की कीमत 17 रुपए और छोटी जिंदगी की कीमत 12 रुपए लगाई गई थी। कहा जा रहा है कि केबल ब्रिज पर घूमने के लिए आए लोगों को 17 रुपए का टिकट खरीदना होता था। बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट था। क्या इसी कमाई के लिए बिना सेफ्टी की गारंटी के पुल खोला गया, खोलने दिया गया? मोरबी हादसे की जांच के लिए स्ढ्ढञ्ज टीम बनाई गई है। लेकिन क्या असली मौत के सौदागरों पर कार्रवाई होगी? या छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर मगरमच्छों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जो फिर से मासूम जिंदगियों पर सौदे लगाते रहेंगे? गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच जारी है और यकीनन कुछ दिनों बाद जांच के कुछ ना कुछ नतीजे तो आ ही जाएंगे।

गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच जारी है और यकीनन कुछ दिनों बाद जांच के कुछ ना कुछ नतीजे तो आ ही जाएंगे। लोगों मौतों से जुड़ी इस बड़ी लापरवाही को लेकर अब कई बातें सामने आ रही हैं।

लोगों मौतों से जुड़ी इस बड़ी लापरवाही को लेकर अब कई बातें सामने आ रही हैं। हादसे को लेकर हैरानी की ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पर शायद ध्यान दिया गया होता तो शायद इतना भयानक मंजर देखने को नहीं मिलता।

पुल खुलने के चार दिन बाद हादसा- बिना किसी की अनुमति के 26 अक्टूबर को इस पुल को फिर से खोला गया था और चार दिन बाद यही पुल सैंकड़ों लोगों की मौत का कारण बन गया। मोरबी नगरपालिका एजेंसी का कहना है कि कंपनी ओरेवा ने पुल खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था। क्या इसमें प्रशासन की चूक नहीं है। जाहिर है पूरी चूक प्रशासन की है। एक आम आदमी तो टिकट लेकर पुल पर जाने को सुरक्षित मान रहा था। ये भी सामने आया है कि पुल की क्षमता 100 लोगों की थी। फिर भी करीब 233 मीटर लंबे पुल पर 500 से यादा लोगों को कैसे भेज दिया गया। जिसकी वजह से क्षमता से यादा लोगों के पहुंचने को भी हादसे की वजह बताया जा रहा है लेकिन इसमें सीधे तौर पर प्रशासन की चूक है। साथ ही मेंटिनेंस करने वाली कंपनी की लापरवाही। अब पुल का मैनजेमेंट करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। कंपनी को मार्च 2022 में ही 15 साल के लिए ठेका मिला था। यानी हादसे से ठीक 6 महीने बाद ही ये बड़ा हादसा हो गया।

त्रिकोणीय होगा मुकाबला

गुजरात का रण कौन जीतता है? मुख्यमंत्री किस दल का होगा? सवाल तमाम हैं जिनका जवाब वक़्त देगा। लेकिन जैसा माहौल सोशल मीडिया पर बनता नजर आ रहा है, वहां भी गुजरात चुनाव लोगों की उत्सुकता के केंद्र में है। जैसे ट्वीट, रिट्वीट और रिप्लाई 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आ रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस और भाजपा हों या फिर आम आदमी पार्टी गुजरात का चुनाव एक नयी राजनीतिक इबारत की रचना करेगा।

समता पाठक

दिसंबर की शुरुआत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारी राजनीतिक दलों द्वारा आखिरकार शुरू हो ही गई है। चुनावों को लेकर तमाम तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं। कई कथाएं हैं जो निर्माणाधीन हैं, वहीं बात मीडिया की हो तो वहां भी अलग अलग चैनल्स अपने ओपिनियन पोल लेकर हमारे सामने हैं। कहीं भाजपा के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है तो किसी चैनल के पैनल पर बैठे एक्सपर्ट्स इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा फायदा कांग्रेस को गुजरात में होगा और वहां उसकी सीटें बढ़ेंगी। इन सब के विपरीत कई राजनीतिक विश्लेषक ऐसे भी हैं जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उग्र रवैये ने हैरत में डाल दिया है। ऐसे लोगों का यही मानना है कि गुजरात में कांग्रेस और भाजपा के लिए आम आदमी पार्टी साइलेंट किलर साबित होगी। चुनाव से पूर्व जैसी हालत है गुजरात में मेहनत सिर्फ आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात का रण कौन जीतता है? मुख्यमंत्री किस दल का होगा? सवाल तमाम हैं जिनका जवाब वक़्त देगा। लेकिन जैसा माहौल सोशल मीडिया पर बनता नजर आ रहा है, वहां भी गुजरात चुनाव लोगों की उत्सुकता के केंद्र में है। जैसे ट्वीट, रिट्वीट और रिप्लाई 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आ रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस और भाजपा हों या फिर आम

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में घटी बीजेपी की सीटें, अब हर क्षेत्र में झोंकी ताकत

गुजरात में नरेंद्र मोदी के सीएम बनने व उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में जितने भी चुनाव हुए हैं, भाजपा की सीटें कम होती रही हैं। पिछले चुनाव में बहुमत से 07 सीटें ज्यादा जीत सकी थी। गुजरात में अपने विरोध में कोई बड़ी विपक्षी ताकत ना होने के बावजूद भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र, हर बूथ को लेकर सजग है। उसने प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेताओं तक को दायित्व सौंप रखा है। भाजपा ना तो कांग्रेस को हल्के में ले रही है और ना ही राय में दस्तक दे रही आम आदमी पार्टी को। दरअसल, गुजरात में नरेंद्र मोदी के सीएम बनने व उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में जितने भी चुनाव हुए हैं, भाजपा की सीटें कम होती रही हैं। पिछले चुनाव में तो वह बहुमत से महज सात सीटें ही ज्यादा जीत पाई थी। ऐसे में पार्टी पिछले 27 साल की अपनी सरकार के खिलाफ किसी तरह के सत्ता विरोधी माहौल को सामने नहीं आने देना चाहती है। इस दौरान पूरी एक नई पीढ़ी आ गई है। पार्टी उसको भी साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। मतदाताओं को उपलब्धियों और भविष्य वादों के जरिए साथ बनाए रखने की कोशिश में है। यही वजह है कि भाजपा राज्य में विभिन्न आयामों को लेकर जनता के बीच आ रही है। चाहे वह खेती हो, उद्योग हो, रक्षा हो, खेल हो या राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानक जिस वर्ग के लिए जो संदेश दे सकता है वह उसको सामने रख आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं। गुजरात में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की प्रमुख नेताओं की टीमें भी जुटी हुई हैं। कुछ नेता तो पिछले दो महीने से राय के दौरे कर रहे थे। अब अधिकांश नेता दीपावली के बाद चुनाव तक पूरे समय राज्य में चुनावी रणनीति में जुटे रहेंगे।

आदमी पार्टी गुजरात का चुनाव एक नयी राजनीतिक इबारत की रचना करेगा।

अभी क्या माहौल है गुजरात में

वाक़ई गुजरात का चुनाव उत्सुकता पैदा करता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर रैलियां सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले ये एक तरह की रस्म-अदायगी है। माना यही जा रहा है कि गुजरात में भाजपा पूरी तरह से अपने परंपरागत वोटबैंक पर आश्रित है। भाजपा के बाद अगर हम कांग्रेस की तैयारियों पर नजर डालें तो चुनाव पूर्व जैसी तैयारी कांग्रेस की है। साफ़ पता चलता है कि गुजरात में कांग्रेस सुप्तावस्था में है और सूबे के अधिकांश नेता राहुल गांधी के साथ

भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस से इतर गुजरात विधानसभा चुनावों में जो तैयारियां आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है वो हैरान करने वाली है। आप गुजरात के लिए खासी गंभीर है। चाहे वो रैलियां और जनसभाएं हों या फिर ट्विटर गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जैसा रुख आम आदमी पार्टी का है वो यक़ीनन आामक नजर आ रहा है। सूबे में केजरीवाल का ऑटो स्टंट अभी से विरोधियों को परेशान करता नजर आ रहा है।

कह सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए गुजरात में रेस चल रही है। तो वर्तमान परिदृश्य में आम आदमी की स्थिति उस खरगोश की तरह है जो पंचतंत्र की उस बरसों पुरानी कहानी में बहुत तेज भागा था लेकिन एक मौका आया वो थक गया और रेस कछुए ने जीती। गुजरात के सन्दर्भ में वो कछुआ कौन होगा इसका फैसला ताजा सूरत ए हाल का आंकलन कर जनता ही करे तो बेहतर है। गुजरात विधानसभा चुनावों में सूबे का नया मुख्यमंत्री कौन और किस दल का होगा? इसका फैसला तो वक़्त करेगा लेकिन अभी जो प्रश्न है वो सीटों का है तो अब जनता ही बताए कि कांग्रेस और भाजपा से लेकर

परिदृश्य में आम आदमी की स्थिति उस खरगोश की तरह है जो पंचतंत्र की उस बरसों पुरानी कहानी में बहुत तेज भागा था लेकिन एक मौका आया वो थक गया और रेस कछुए ने जीती। गुजरात के सन्दर्भ में वो कछुआ कौन होगा इसका फैसला ताजा सूरत ए हाल का आंकलन कर जनता ही करे तो बेहतर है। गुजरात विधानसभा चुनावों में सूबे का नया मुख्यमंत्री कौन और किस दल का होगा? इसका फैसला तो वक़्त करेगा।

आम आदमी पार्टी ने दिलचस्प बनाया चुनाव

राज्य में अभी तक के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर दिखी है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के उतरने से कयास लगाए जा रहे हैं कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसे चुनावी वादे किए हैं। उधर चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी ने समान नागरिक संहिता पर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी बनाने का ऐलान करते हुए बड़ा दांव खेला है। गुजरात में 1995 से सिर्फ एक साल के अंतराल को छोड़कर बीजेपी लगातार सत्ता में रही है। पिछले 24 साल से राय में भाजपा की सरकार है। ऐसे में सबकी नजर इस बार के चुनाव पर टिकी हैं। सवाल है कि क्या इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा या भाजपा का जादू बरकरार रहेगा? राज्य में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता था, इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई है।

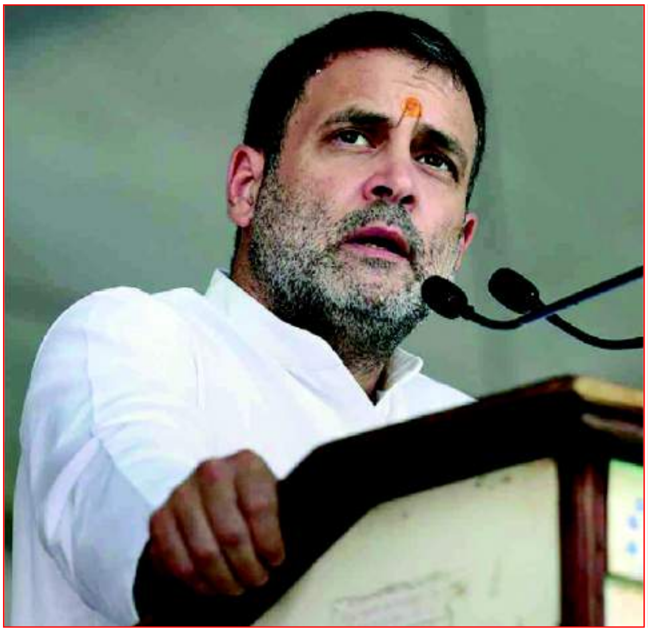

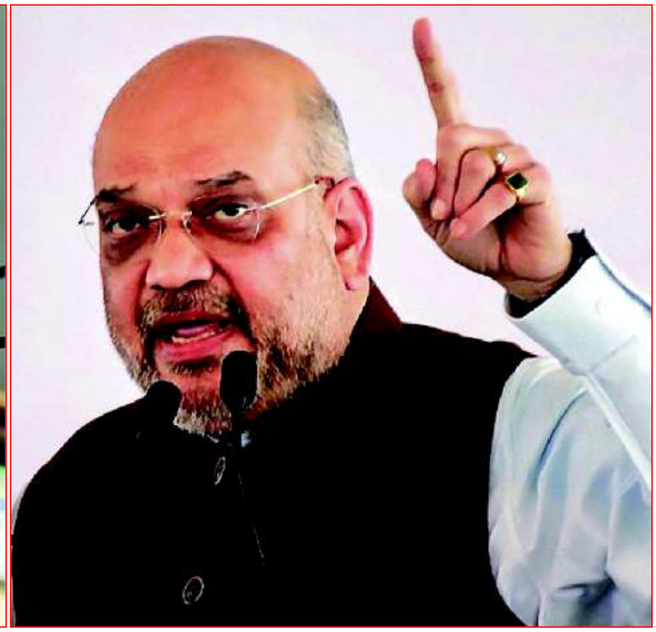

आम आदमी पार्टी तक गुजरात में किसकी मेहनत रंग लाती है? और बढ़ी हुई सीटें किसके पाले में आती हैं।

मतदाताओं के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश

भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है। चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में। वह मतदाताओं की हर वर्ग तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। गुजरात में भी उसी रणनीति पर आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि पिछले

विधानसभा चुनाव में विपक्ष के बड़े मुद्दे

किसान

पिछले दो साल से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मुद्दा हावी है। कृषि कानून के बाद से इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में भी ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों का नहीं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटी है।

बेरोजगारी

चुनाव रैलियों के दौरान विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा। युवाओं में रोजगार के कम अवसर की वजह असंतोष की बातें में लगातार आती रही हैं। भर्ती परीक्षाओं में देरी का भी मुद्दा हावी रह सकता है। क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन गया है।

मंहगाई

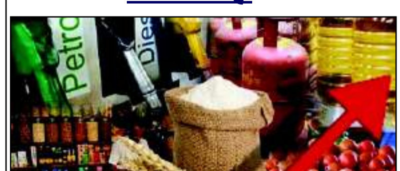

राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा हावी रहा है। इसका असर गुजराज चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अभी से विपक्षी दलों के नेता महंगाई पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर भी सरकार निशाने पर है।

विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे हैं उनको वह नजरअंदाज नहीं कर सकती है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2002 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से सीटें कम हो रही हैं।

आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 77 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। बीजेपी को 49 प्रतिशत और कांग्रेस को 41 प्रतिशत से यादा वोट मिले थे। पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा रह चुके हार्दिक पटेल इस बार बीजेपी के खेमे में हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी थी, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में गुजरात के रण पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले शुरू की थी। अब तक आम आदमी पार्टी ने राज्य की 80 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।

बीजेपी ने इस बार रखा 150 का टारगेट

2017 के विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। उस चुनाव में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी की युवा तिकड़ी ने चुनाव को नजदीकी बना दिया था। हालांकि इस बार ये तिकड़ी सीन में नहीं है। अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी ऐक्टिव नहीं दिख रहे। बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ली हुई है। हाल ही में गुजरात दौरे में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया है। शाह ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 150 प्लस का लक्ष्य रखा है।

गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 77 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। बीजेपी को 49 प्रतिशत और कांग्रेस को 41 प्रतिशत से यादा वोट मिले थे।

2017 चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें

2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। वहीं कांग्रेस ने 177 सीटों पर चुनाव लड़कर 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2, एनसीपी को एक और निर्दलीय को 3 सीटों पर कामयाबी मिली थी। बीजेपी ने 49.05 प्रतिशत, जबकि कांग्रेस ने 41.44 प्रतिशत वोट हासिल किए थे।

क्या इस बार बदलेंगे समीकरण ?

यूं तो पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में

प्रियंका गांधी - कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी वह यात्रा पर रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। प्रियंका में राय के चुनाव प्रचार में सयि भूमिका में दिखाई देंगी। इसके साथ ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का एलान भी हो चुका है। इसके बाद नए अध्यक्ष की पहली परीक्षा गुजरात और हिमचाल चुनाव में ही होनी है।

चुनाव प्रचार के प्रमुख चेहरे

नरेंद्र मोदी - 2014 के बाद चुनाव कहीं भी हों, भाजपा के लिए चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही होते हैं। गुजरात में तो भाजपा के लिए तो सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी का ही हैं। मोदी 12 साल से भी ज्यादा समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी का ज्यादातर राजनीतिक समय गुजरात में ही बीता है। मोदी ने अभी से रैलियां भी शुरू कर दी हैं। फिलहाल वह सरकारी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कर रहे हैं।

अमित शाह - पीएम मोदी के बाद गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए दूसरा सबसे बड़ा चेहरा गृहमंत्री अमित शाह का होगा। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से सांसद हैं। गुजरात के ही रहने वाले हैं और राजनीति स्तर पर आने से पहले इनकी पूरी राजनीति गुजरात पर ही फोकस रही है।

अरविंद केजरीवाल - पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के बाद अरविंद केजरीवाल का मनोबल काफी बढ़ गया है। यही कारण है कि उन्होंने इस बार पीएम मोदी के गृहराय गुजरात में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चुनाव प्रचार में प्रमुख चेहरे हैं।

मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस में 2017 के कई बड़े चेहरे इस बार साथ पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हार्दिक पटेल का है। हार्दिक ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली है। 2017 में हार्दिक ने गुजरात में पाटिदार आंदोलन करके बड़ा नाम कमाया था। उनके साथ जिग्नेश मेवानी जैसे कई युवा कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। अब हार्दिक भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री पद के चेहरे

भूपेंद्र भाई पटेलः भाजपा के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब होती है, तो भूपेंद्र भाई पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। चुनाव से 15 महीने पहले विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए थे और पार्टी ने जीतने के बाद उन्हें फिर से सीएम बनाया गया था।

जगदीश भाई मोतीजी ठाकोरः गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जगदीश भाई भी कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की रेस में हैं। हालांकि, अभी पार्टी ने किसी भी नाम का एलान नहीं किया है। जगदीश भाई के अलावा कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल, जिग्नेश मेवानी व कुछ अन्य नेता भी इस दौड़ में हैं।

गोपाल इटालिया : आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी सीएम पद की रेस में हैं। अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो गोपाल इटालिया पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। गोपाल इन दिनों काफी विवादों में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।

भाजपा के क्या हैं मुद्दे ?

भाजपा ने विकास, राष्ट्र सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीबों-किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान पर उतरने का फैसला लिया है। भाजपा हर जगह अपने विकास कार्यो की गिनती करा रही है। एम्स, आईआईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को बनाने की बात कह रही है। हाईवे, पुल, अंडर ब्रिज, टनल, मेट्रो जैसे अन्य कार्यो को बताकर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है।

उज्जैन : भारत का एक अत्यन्त प्राचीन गौरवशाली नगर

अभी-अभी मध्यप्रदेश शासन ने श्री महाकाल महाराज विकास योजना में एक विशाल और भव्य महाकाल लोक का निर्माण कराया है। यह महाकाल लोक न केवल अत्यन्त भव्य और दिव्य है अपितु समूचे महाकाल परिसर को एक नूतन आभा प्रदान करता है। इसके निर्माण में उज्जयिनी की पूरी सांस्कृतिक विरासत की झलक हमें मिलती है। इसके कारण उज्जैन में और मध्यप्रदेश में पर्यटन की बहुत संभावनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जायेंगी। यों एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उज्जैन नगर की पहचान पहले से सारे विश्व में है किन्तु इस महाकाल लोक के निर्माण से वह और भी विश्व के आकर्षण का केन्द्र बनेगी और पूरे प्रदेश को एक नई पहचान देगी।

अब हम आते हैं उज्जयिनी के प्राचीन गौरव एवं इतिहास पर। उज्जयिनी - पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता भगवान महाकाल द्वारा अधिष्ठित नगरी, पावन क्षिप्रा के तट पर अवस्थित यह पुराण प्रसिद्ध नगरी, पृथ्वी के नाभि-स्थल पर स्थित हजारों वर्षो से विश्व की सभ्यताओं के आकर्षण का केन्द्र रही है। सभ्यता और संस्कृति की अनेक धाराओं का संगम उज्जयिनी में था, चाहे वह व्यापार-व्यवसाय की धारा हो अथवा विभिन्न धर्मो की धारा हो या विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की। सच में यह पृथ्वी का केन्द्र स्थल है, क्योंकि यहाँ से एक ओर पूर्व से पश्चिम जाने वाली कर्क रेखा गुज़रती थी तो उत्तर में सुमेरू से लंका तक जाने वाली शून्य रेखा भी उज्जयिनी से होकर ही गुज़रती थी। इसलिये पुराणों में उज्जयिनी को शरीर के आठ चक्रों में से मध्य चक्र मणिपुर में अवस्थित बताया गया

है।

आज्ञाचक्रं स्मृता काशी या बाला श्रुतिमूर्धनि
स्वाधिष्ठानं स्मृता कांची मणिपूरमवन्तिका
नाभिदेशे महाकाल स्तन्नाम्ना तत्र वै हरः (वाराहपुराण)

सूर्य सिद्धान्त सिद्धान्त शिरोमणि तथा पंचसिद्धांतिका - ज्योतिष के तीनों प्रसिद्ध ग्रंथों में उज्जयिनी को पृथ्वी के नाभि-स्थल पर अवस्थित बताया गया है। सूर्य सिद्धान्त के अनुवादक प्रसिद्ध विद्वान् ई. बर्जेस ने लिखा है कि उज्जैन नगरी की स्थिति ने इसको विश्व के प्रमुख रेखांश पर अवस्थित बताया है। जो गौरव आज ग्रीनविच को मिला है, वही गौरव प्राचीन काल में उज्जयिनी को प्राप्त था। भारतीय सिद्धान्त ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की गणना अभी भी उज्जैन मध्य रात्रि के आधार पर की जाती है। बर्जेस ने लिखा है कि उज्जयिनी समृद्ध मालवा प्रान्त की राजधानी रहा है तथा अत्यन्त प्राचीन समय से भारतीय साहित्य, विज्ञान और कलाओं का केन्द्र रहा है। भारतवर्ष के सभी सांस्कृतिक केन्द्रों में से यह प्रसिद्ध समुद्री रास्ते के अत्यन्त समीप था और इसलिये ईसा की प्रारंभिक शदियों में अलेक्जेड्रिंया तथा रोम से भारतीय व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। विश्व सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यहाँ पर भारत के अनेक प्रान्तों के सिक्के मिले हैं। गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी अत्यन्त स्पृहा और स्नेहिल वाणी के साथ अपनी एक कविता में उज्जैन का स्मरण किया है।

दूर बहुत दूर ....
स्वप्न-लोक में उज्जयिनी-पुरी में
खोजने गया था कभी शिप्रा-नदी के पार,
अपनी पूर्व-जन्म की पहली प्रिया को
मुख पर थी उसके लोध्र-रेणु, लीला-पद्म हाथ में,
कर्ण-मूल में कुन्द-कली, कुरूबक माथे पर।
तनु देह पर रक्ताम्बर बांधा था नीवीबन्ध पर
चरणों में नूपुर बजते थे रह-रह कर बसन्त के दिन
फिरा था दूर-दूर पहचाने पथों पर

जब हम इसके इतिहास पर जाते हैं तो महाभारत में यह अपने पूर्ण गौरव के साथ उपस्थित है। विन्द और अरविन्द नाम के राजा महाभारत काल में अवन्ती पर राज करते थे, जिन्होंने उस महासमर में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। उनकी एक बहन मित्रवृन्दा थी, जो भगवान कृष्ण की पटरानियों में से एक बनी।

कालिदास ने अत्यन्त रमणीय शब्दों में भगवान महाकाल और इस सुन्दर नगरी का वर्णन किया है। मेघदूत में वे अपने मेघ को निर्देश देते हैं कि यद्यपि तुम्हारा मार्ग वक्र

होने से कुछ लम्बा हो जायेगा किन्तु उज्जयिनी नगरी का अवलोकन अवश्य करना। उज्जयिनी नगरी को देखकर ऐसा लगता है मानों स्वर्ग में अवस्थित पुण्यात्मा जन पृथ्वी पर स्वर्ग के ही एक दीप्तिमान खण्ड लेकर आ हो गये हों -

स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां
शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत् खण्डमेकम् (Meghaduta 1/30)

ब्रह्मपुराण तथा स्कन्दपुराण ने उज्जयिनी का अत्यन्त विस्तृत और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है।

यह महानगरी सुन्दर देवालयों से सुशोभित है तथा दृढ़ प्राकार और तोरणों से युक्त है। हृष्ट-पुष्ट स्त्री-पुरूषों से भरी हुई है। सुन्दर मार्ग तथा वीथियाँ हैं व सुविभक्त चौराहे हैं। यह अत्यन्त समृद्ध है तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता-विद्वानों से समलंकृत है। यही कारण रहा है कि इस नगरी के अनेक नाम पुराणों में प्रसिद्ध हो गये जैसे कनकश्रृंगा (जिसके कलश सोने के हों), पद्मावती, कुशस्थली, प्रतिकल्पा इत्यादि।

यहाँ धार्मिक सम्प्रदायों का संगम है। स्कंदपुराण के अवन्ती खण्ड में यह विवरण दिया गया है कि यहाँ पर चौरासी महादेव, आठ भैरव, एकादश रूद्र, द्वादश आदित्य, छह विनायक, चौबीस देवियाँ, दस विष्णु तथा नव नारायण विराजमान हैं। हिन्दू धर्म के तीनों प्रमुख सम्प्रदाय अर्थात् शैव, वैष्णव तथा शाक्तों के अतिरिक्त यह नगरी जैन तथा बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केन्द्र रही है।

इसी प्रकार क्षिप्रा नदी का महत्व भी पवित्र गंगा, नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के सदृश बताया गया है। यदि तीर्थयात्री एक बार भी इसके तट पर आकर स्नान कर ले तो क्षण भर में ही उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह नदी चन्द्रमा से उत्पन्न होने के कारण अमृत से भरपूर है और इसलिये सोमवती भी कहलाती है।

नास्ति वत्स महीपष्ठे शिप्रायाः सदृशी नदी।
यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः सकृदासेवितेन वै।।

उज्जयिनी का वास्तविक इतिहास छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जब चण्द्रप्रद्योत यहाँ का राजा था। उसकी पुत्री वासवदत्ता और वत्सराज उदयन की प्रेम कथाओं से यहाँ का जनमानस भलीभांति परिचित था, जिसका उल्लेख कालिदास ने भी अपने मेघदूत में किया है। पुराणों के अनुसार वीतिहोत्र वंश के अंतिम राजा की हत्या पुनिक द्वारा की गई थी, जिसने अपने पुत्र प्रद्योत को यहाँ का राजा बनाया। उसके समय में उज्जयिनी अत्यन्त समृद्ध हुई और उसकी सत्ता का क्षेत्र बहुत व्यापक बना। मौर्यो के समय में जब चन्द्रगुप्त मौर्य सम्राट बना तब उसका पुत्र बिन्दुसार यहाँ का प्रान्तीय शासक था और जब बिन्दुसार ने

सत्ता संभाली तब उसका पुत्र अशोक यहाँ प्रान्तपाल बना। उसके पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा की शिक्षा-दीक्षा उज्जयिनी में ही हुई और यहीं से वे बौद्ध धर्म का प्रसार करने हेतु लंका गये। शुंग वंश का राजा अग्निमित्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम् का नायक है। जो इसका प्रमाण है कि इस क्षेत्र में शुंग वंश का प्रभुत्व रहा। शुंगों पर विक्रमादित्य के पिता गर्दभिल्ल ने विजय प्राप्त की, जो शकों के द्वारा परास्त हुआ किन्तु उसके पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर ईसा पूर्व पहली शताब्दी में यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया। महाराजा विक्रमादित्य अपने ऐश्वर्य, अति मानवीय पराक्रम, दानशीलता और न्यायप्रियता के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए, जिनका चलाया हुआ विक्रम संवत् आज भी प्रचलित है। यह संवत् ईसा पूर्व 57 में प्रारंभ हुआ। इनके ही भाई प्रसिद्ध भतृर्हरि हुए जिन्होंने प्रसिद्ध शतक त्रयी - श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक लिखे तथा जो बाद में गोरख सम्प्रदाय में दीक्षित होकर विरक्त साधु हो गये थे। विक्रमादित्य के बाद रूद्रदामन, यशोधर्मन तथा हर्ष विक्रमादित्य इस क्षेत्र के अधिपति हुए। कुछ समय के लिये राष्ट्रकूटों के आधिपत्य में रहकर अवन्ती 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं के आधिपत्य में आ गई जिसके प्रथम राजा मुंज थे तथा उनके भतीजे राजा भोज ने उज्जैन से हटा कर धार को अपनी राजधानी बनाया। भोज पराक्रमी राजा होने के साथ-साथ बहुत बड़े विद्वान्, कवि और विद्वानों के प्रशंसक थे। उन्होंने ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाखाओं के विद्वानों को अपने यहाँ एकत्र किया और विभिन्न विषयों के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना उनके काल में हुई। उसके वंशज नरवर्मा ने महाकाल मंदिर का उद्धार किया और भगवान महाकाल के प्रति एक स्तोत्र की भी रचना की, जिसे आज भी वहाँ देखा जा सकता है।

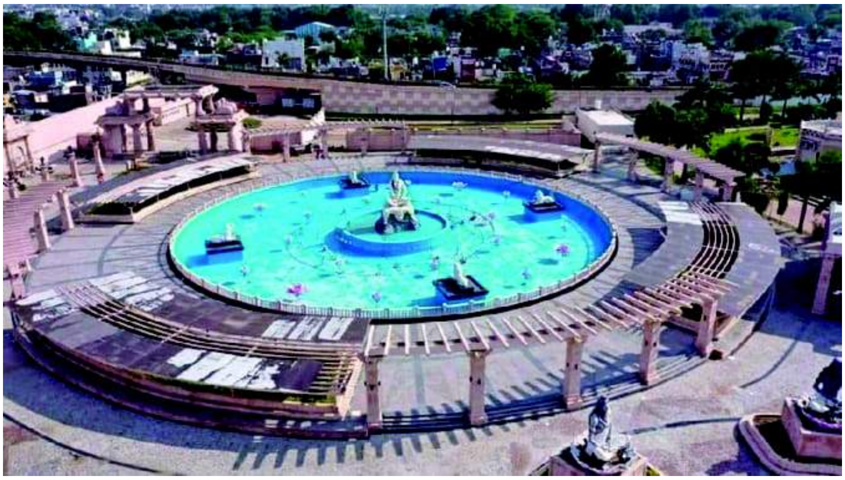

13वीं सदी के प्रारंभ में उज्जयिनी को बुरे दिन देखने पड़े, जब सन् 1234 में सुल्तान अल्तमस ने इस पर आक्रमण किया तथा महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया। मुगल सम्राट अकबर तथा जहांगीर भी उज्जैन आये थे तथा कालियादेह महल में ठहरे थे, जिसे राजा महमूद खां ने सन् 1437 में बनवाया था। 18वीं सदी में मुगलों के अधीन सवाई जयसिंह उज्जैन के प्रांतीय शासक बने। वे ज्योतिर्विज्ञान के बड़े अनुरागी थे और उन्होंने उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा दिल्ली में चार वेधशालाएँ बनवाईं। उज्जैन की वेधशाला से आज भी वेध लिये जा सकते हैं। सन् 1732 में मुगल तथा मराठाओं की एक संधि के अन्तर्गत यह क्षेत्र मराठाओं के अधीन आ गया। इसके साथ ही उज्जैन का पुनर्निमाण प्रारंभ हुआ। राणौजी सिंधिया के प्रधानमंत्री बाबा रामचन्द्र सुकतनकर ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और अनेक मंदिर बनवाये। क्षिप्रा तट का प्रसिद्ध रामघाट संभवतः उन्हीं के समय में बना और ऐसा प्रतीत होता है कि तभी से सिंहस्थ की परम्परा प्रारंभ हुई। सन् 1807 तक उज्जैन ही सिंधिया राजवंश की राजधानी रही, इसके बाद उसे ग्वालियर ले जाया गया। पूरे ब्रिटिश शासनकाल में उज्जैन ग्वालियर रियासत का एक संभागीय मुख्यालय बना रहा।

वर्तमान उज्जैन पश्चिम रेल्वे के भोपाल-रतलाम सेक्शन पर अक्षांश 230'- 11/ तथा रेखांश 750-46/ पर मालवा के पठार पर अवस्थित है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है तथा रेल और सड़क मार्ग से यह शहर अनेक प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। शहर शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र है, जहाँ पर 2 विश्वविद्यालय तथा अनेक शैक्षणिक संस्थाएँ हैं। मध्यप्रदेश शासन का यह संभागीय मुख्यालय है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर और पवित्र क्षिप्रा नदी के अतिरिक्त यहाँ पर गोपाल मंदिर, हरसिद्धि पीठ, चिंतामण गणेश, मंगलनाथ, महर्षि सांदीपनि पीठ, महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान, महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक, कालभैरव तथा कालिदास अकादमी जैसे संस्थान तथा मंदिर हैं। इसे मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है।

लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और धार्मिक-ऐतिहासिक अध्येता हैं।

ग्रामीण पेयजल के लिए समय अनुरूप बदलते संसाधन

देश की आजादी और फिर राज्य का गठन जैसी घटनाओं का साक्ष्य इतिहास के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कल, आज और कल के पूरे परिदृश्य में जल प्रत्येक जीव की पहली जरूरत रही है। कालांतर में ग्रामीण आबादी की पेयजल व्यवस्था के स्रोत कुआँ, बाबड़ी, तालाब, पोखर और नदियाँ जरूर रहे हैं, लेकिन परिवार की जल व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी आधी आबादी (महिलाओं) पर ही रही है। पानी के स्त्रोत कितनी भी दूर हों और मौसम कैसा भी दुष्कर, पर पानी लाने का काम माँ, बहन, बहू और बेटियों को ही करना होता था।

मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना (एक नवंबर 1956) के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का गठन वर्ष 1969 में हुआ। विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय की योजनाएँ तैयार कर क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जहाँ पेयजल के स्त्रोत नहीं थे, वहाँ पर केलिक्स-रिंग मशीन द्वारा हैण्डपंप स्थापित कर आम जनता को शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती रही है। इस व्यवस्था के लिए करीब 5 लाख 55 हजार हैण्डपंप की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी, जो लगातार क्रियाशील है। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल प्रदाय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन सहित पेयजल स्त्रोतों की जल-गुणवत्ता की

निगरानी और अनुश्रवण सहित सहायक गतिविधियों का संचालन भी निरंतर हो रहा है। केन्द्र सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान आधारित गतिवर्धित ग्रामीण जल-प्रदाय कार्यक्रम पर वर्ष 1972 से अमल शुरू हुआ। इसमें 40 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन के मान से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के कार्य किए गए।

त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बाद वर्ष 1995 में नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय के संचालन और संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकायों को सौंपा गया। इसके बाद से ही पीएचई विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मापदंड और गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के दायित्व का निर्वहन कर रहा है।

त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बाद वर्ष 1995 में नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय के संचालन और संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकायों को सौंपा गया। इसके बाद से ही पीएचई विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मापदंड और गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के दायित्व का निर्वहन कर रहा है।

समय के अनुरुप होते परिवर्तन

प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के लिए समय के अनुरूप बदलाव की आवश्यकता और सुगमता को देखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री पेयजल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्य प्रारंभ किये गये। इनमें ग्रामीण आबादी के घरों में नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। केंद्र, राज्य और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से अप्रैल 2020 तक 17 लाख 72 हजार ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन से जल

पहुँचाया गया।

मिशन ने दी ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को नई दिशा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का देश की ग्रामीण आबादी के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ऐसा वरदान है जो उनकी पेयजल की कठिनाइयों को पूरी तरह दूर कर देगा। आजादी के बाद श्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ग्रामीण परिवारों की पेयजल व्यवस्था की बड़ी कठिनाई को समझा, उस पर गंभीरता से चिंतन किया और निदान के लिये जल जीवन मिशन की घोषणा कर उसे मूर्तरूप दिया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की करीब सवा पांच करोड़ ग्रामीण आबादी के लिए जल जीवन मिशन में तत्काल कार्य प्रारंभ करवाये। मिशन को सरकार की प्राथमिकता में रख कर निरंतर प्रगति की समीक्षा करते हुए जल प्रदाय योजनाओं के कार्य गुणवत्तापूर्ण और जल्दी पूरा करने के लिए विभागीय अमले से संवाद कर उन्हें प्रेरित किया। जून 2020 में मिशन के कार्य जब प्रारंभ हुए तो देश के साथ मध्यप्रदेश भी कोविड-19 के लॉकडाउन से गुजर रहा था। कोविड-19 और दो वर्षा काल के बाबजूद 20 लाख से अधिक वार्षिक लक्ष्य वाले 12 बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश ने अपना अच्छा स्थान लगातार बनाये रखा है।

मिशन में मध्यप्रदेश के बुरहानपुर को देश का शत-प्रतिशत हर घर जल सर्टिफाइड जिला होने का प्रथम पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु से प्राप्त हुआ है। अब तक प्रदेश के 6 हजार 783 ग्राम शत-प्रतिशत हर घर जल युक्त हो चुके हैं, इनमें से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक सर्टिफाइड घोषित ग्रामों की संख्या मध्यप्रदेश की ही है। अब तक प्रदेश के 53 लाख 97 हजार 911 ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँचाया जा चुका है। इसी श्रंखला में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित 41 हजार 271 आँगनवाड़ियों और 71 हजार 92 शालाओं में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गई है। शेष शालाओं एवं आँगनवाड़ियों में भी नल कनेक्शन के कार्य निरंतर जारी हैं। हमारा प्रदेश 12 बड़े राज्यों में सर्वाधिक ग्रामों को शत-प्रतिशत हर घर जल उपलब्ध करवाने में दूसरे पायदान पर है।

विभाग की मिशन की व्यूह-रचना में प्रदेश के करीब एक करोड़ 20 लाख लक्षित ग्रामीण परिवारों में से शेष रहे परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 की समय-सीमा में नल कनेक्शन से जल पहुँचाना है। विभागीय सर्वेक्षण में 10 हजार 409 ग्राम स्त्रोत विहीन पाये गये हैं। राज्य शासन ने इन ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं के लिए जल-स्त्रोत आकलन समिति गठित की है, जो वैकल्पिक स्त्रोत के संबंध में सूक्ष्म परीक्षण कर रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर जल-संरचनाओं के निर्माण के कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे।

आने वाला कल-हर घर होगा जल

केन्द्र और राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत व्यय भार से संचालित जल जीवन मिशन में अब तक 49 हजार 776 करोड़ रूपये लागत की जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें 36 हजार 464 करोड़ की समूह और 13 हजार 312 करोड़ की एकल जल-प्रदाय योजनाएँ शामिल है। मिशन में प्रदेश के लक्षित 51 हजार 548 ग्रामों में से 41 हजार 139 में जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। शेष जल-स्त्रोत विहीन ग्रामों के संबंध में राज्य स्तरीय समिति आकलन का कार्य कर रही है।

प्रदेश के 23 हजार से अधिक ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य 60 से 90 प्रतिशत प्रगतिरत हैं। जल-स्त्रोत विहीन ग्रामों का सर्वे कार्य शुरू किया जा चुका है। मिशन में लक्ष्य से भी बड़े अपने हौंसले के साथ हम निश्चित ही अपेक्षित और सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। आने वाला कल प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुँचाने के उद्देश्य की पूर्ति का साक्षी होगा।

लेखक, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है।

केजरीवाल ही असली हिंदू हृदय सम्राट हैं!

अमित राय

केजरीवाल ने दिवाली पर देश के विकसित होने का जो केजरीवालत्व प्राप्त किया था उसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेस में उन्होंने कहा- हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल दौर में है। हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया हर रोज कमजोर होता जा रहा है। आम आदमी को इसकी मार भुगतनी पड़ती है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि इसे दुरुस्त करने के लिए कोई बड़ा फैसला ले। बहुत सारे फैसले लेने की जरूरत है, खूब स्कूल और अस्पताल बनाने हैं। सड़क और मूलभूतढांचों को तैयार करना है। बावजूद कोशिशें तब नतीजा देती हैं, जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। उन्होंने कहा- ऐसा क्यों हैं कि आजादी के 75 साल होने के बावजूद हम आज भी विकासशील देश हैं। हमारी गिनती गरीब देशों में है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित और अमीर देश बने। हर भारतवासी, हर परिवार अमीर बने। लक्ष्मीजी समृद्धि की देवी हैं। वहीं गणेशजी सभी विघ्न को दूर करते हैं। इसलिए उन दोनों की तस्वीर नोटों पर लगनी चाहिए। गांधी जी के साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगनी चाहिए। एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ भगवान। इससे पूरे देश को आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए हमें सारे नोट बदलने की जरूरत नहीं है बल्कि नए नोटों के साथ यह शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे। केजरीवाल ने खुद बताया कि उन्हें यह ज्ञान गणेश-लक्ष्मी पूजन के दौरान मिला। अखिलेश यादव (सपने में कृष्ण आए थे) और तेजप्रताप यादव (साईं बाबा ने सपने में भभूत भेंट की थी) के बाद केजरीवाल ने ईश्वर और आत्मा से संवाद के बाद नोटों पर महात्मा गांधी के साथ गणेश-लक्ष्मी की फोटो देखने की लालसा के साथ साफ़ कर दिया कि वही असली हिंदू हृदय सम्राट हैं।

Festivals and the Environmental Pollution

Gatik Dewani

India is known for its festivals. Festivals commemorate the shift in the seasons, harvest, unity, and the birth celebrations of divinities, holy men, and goddesses and gods. When it comes to their faith, Indians have a range of practices such as fasting, celibacy, and so on. While we look forward to enjoying festivals with great joy, take a moment to read this article prior to actually heading out to buy fireworks this Diwali.

Each year, firecrackers are set off during festivals such as Diwali, as well as private celebrations and festivities, resulting in the release of harmful smoke and grave air pollution. The bursting of fireworks causes an annual increase in the level of Respirable Suspended Particulate Material (RSPM) in the air. RSPM are minute particles that have been linked to a variety of health conditions, including bronchitis and asthma, further affecting all the age groups of human beings.The bursting of crackers also creates a huge mess.Likewise, the idol immersion areas are littered with

flowers and idol parts every year during the Muharram, Ganesh festivities and Durga Puja. These idols are made of plaster of Paris, and the paint used on them contains significant amounts of heavy metals. After a few days of immersion, the toxin levels in the water bodies rise dramatically. These toxins ultimately enter the food chain and have an impact on the marine ecosystem and biodiversity. Correspondingly, many water sources are contaminated by paint, hazardous synthetic materials, and recklessly discarded plastic waste.

Concerning the noise

pollution, high - pitched loudspeakers, firecrackers, and loud musical instruments are the leading causes of noise pollution in our country. With the advent of urban development, people in metropolitan areas have to deal with the issue of noise pollution in their daily ordinary routine. Each type of festive ceremony, especially during festivals, only exacerbates this issue. A study conducted by the World Health Organization (WHO) proves that noise pollution is not only a problem to the environment, but it also poses a significant threat to human health as well. Citizens have repeatedly violated the permissible noise limit, which is currently set by the Supreme Court at 55 decibels for the day and 45 decibels at night, during various festivals such as Navratri, Dussehra, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Durga Puja, and Diwali. Even though local governments may make every effort to maintain decorum during festivals, but we as responsible citizens must also exercise caution when it comes to noise pollution. Despite being well aware, we do not take the health a consequence of repeated exposure to such high-decibel sounds sincerely. Correspondingly, noise pollution has a negative impact on young children as well as adults, causing sleep disruption,

A study conducted by the World Health Organization (WHO) proves that noise pollution is not only a problem to the environment, but it also poses a significant threat to human health as well. Citizens have repeatedly violated the permissible noise limit, which is currently set by the Supreme Court at 55 decibels for the day and 45 decibels at night, during various festivals such as Navratri, Dussehra, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Durga Puja, and Diwali.

hypertension, tinnitus, and acute hearing loss. Furthermore, excessive noise can be frightening and, in some cases, potentially deadly to animals.

Regarding the waste generation and management, a massive amount of dry waste is generated both during and after festivals. During festivals such as Diwali, dry waste increases due to firecrackers because there isn't enough space to dispose it off, and other ignored constraints. Another source of concern is the amount of waste discarded from pooja pandals, which includes papers,dried flowers and incense. In regard to this, the local government bodies, and the individuals, should adapt more environmentally safe behavior, for the solid waste disposal.

Festivals are extremely important in our lives. People are believed to forget their differences at festivals, which mark a new beginning for them. Festivals literally are a symbol of happiness, harmony, and enjoyment in our lives. However, while enjoying these festivals, we must keep environment friendly and sustainable practices in mind.

Festivals are extremely important in our lives. People are believed to forget their differences at festivals, which mark a new beginning for them. Festivals literally are a symbol of happiness, harmony, and enjoyment in our lives. However, while enjoying these festivals, we must keep environment friendly and sustainable practices in mind. Considering all these issues, major societal engagement is required to educate people about the benefits of eco-friendly celebrations. For instance, across the country, artisans are making an effort to create environment friendly idols. For example, idol makers in Kolkata, went ahead this year to reduce toxic waste levels by embellishing the idols with paints free of various heavy metals. As a result, many people throughout the country are becoming increasingly aware and opting for eco-friendly idols and decorations for their celebrations. More such initiatives, however, are required throughout the country.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.